अध्याय IV

वाणिज्यिक बैंकों के कार्य और निष्पादन

घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी और उत्साहहीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी रिकवरी की पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संवृद्धि लगातार दूसरे वर्ष 2012-13 में भी धीमी रही। ऋण संवितरण में कमी और ब्याज दरों में गिरावट के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभ में भी गिरावट आयी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी स्पष्ट रूप से गिरावट आयी। सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित भारतीय बैंकों की पूंजी की स्थिति मजबूत बनी रही और यह किसी भी अप्रत्याशित हानि का सामना करने के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर बनी रही। बैंकरहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग की पहुंच में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई क्योंकि वित्तीय समावेशन योजना ने तीन साल पूरे कर लिए हैं। अल्पावधि में, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होगी जिससे आर्थिक रिकवरी में सहायता मिले, साथ ही उसे आस्ति गुणवत्ता के बारे में भी सतर्क रहना होगा। मध्यावधि से दीर्घावधि में, कार्यकुशलता में अनवरत सुधार और समावेशन चिंता के प्रमुख विषय बने रहेंगे।

1. परिचय

4.1 भारतीय वित्तीय परिदृश्य में बैंकिंग क्षेत्र का प्रभुत्व है जिसमें अर्थव्यवस्था[1] के कुल वित्तीय प्रवाह में बैंकिंग प्रवाह का हिस्सा आधे से अधिक है। बैंक न केवल अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए बल्कि वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने वैश्विक वित्तीय संकट के तत्काल बाद काफी आघात-सहनीयता का प्रदर्शन किया, पर यह पिछले दो वर्षों के वैश्विक और घरेलू आर्थिक मंदी से प्रभावित हुआ है। मंद घरेलू संवृद्धि की पृष्ठभूमि में, वर्ष 2011-12 में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र संवृद्धि में गिरावट के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता[2] में भी गिरावट देखी गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में और अधिक मंदी का असर वर्ष 2012-13 में बैंकों के कार्य-निष्पादन पर भी पड़ा, हालांकि मुद्रास्फीति के दबाव में कुछ कमी आई जिसके कारण कम ब्याज दर का माहौल तैयार हुआ।

4.2 इस पृष्ठभूमि में, 89 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों[3] के आंकड़ों को लेते हुए इस क्षेत्र के तुलन-पत्र, लाभ और वित्तीय सुदृढ़ता की प्रवृत्तियों को सामने लाने के लिए, इस अध्याय में वर्ष 2012-13 की भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में पिछले वर्ष/वर्षों के साथ एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई है। इस अध्याय में अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्र से निकटता से जुड़े दो खंडों नामतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों का अलग से विश्लेषण करने के अलावा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन से जुड़े अन्य पहलुओं जैसे ऋण के क्षेत्रवार वितरण, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी विकास और उनके विदेशी परिचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

[1] भारतीय अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह खाते के आधार पर अनुमानित।

[2] आरबीआई, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2011-12।

[3] इसमें 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके पांच सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नए बैंक, निजी क्षेत्र के 13 पुराने बैंक और 43 विदेशी बैंक शामिल हैं।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्र परिचालन

लगातार दूसरे वर्ष तुलन-पत्र की वृद्धि दर में कमी आई, सबसे ज्यादा कमी ऋण वृद्धि में पायी गयी

4.3. वर्ष 2011-12 की प्रवृत्ति के अनुरूप ही, वर्ष 2012-13 में बैंकों के तुलन-पत्र की समग्र वृद्धि में और अधिक कमी आयी (सारणी IV.1; परिशिष्ट सारणी IV.1)। इस कमी का मुख्य कारण बैंक ऋण रहा। ऋण की वृद्धि में कमी आंशिक तौर पर वास्तविक आर्थिक गतिविधियों में मंदी के साथ-साथ बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी को दर्शाती है (चार्ट IV.1)। मार्च 2012 की तुलना में मार्च 2013 में ऋण वृद्धि में मंदी भारतीय स्टेट बैंक समूह के अलावा सभी बैंक समूहों में देखा जा सकती है(चार्ट IV.2)[4]।

चार्ट IV.1: बैंक ऋण में हुई वृद्धि की चुनिंदा आर्थिक और बैंकिंग एग्रिगेट के साथ तुलना

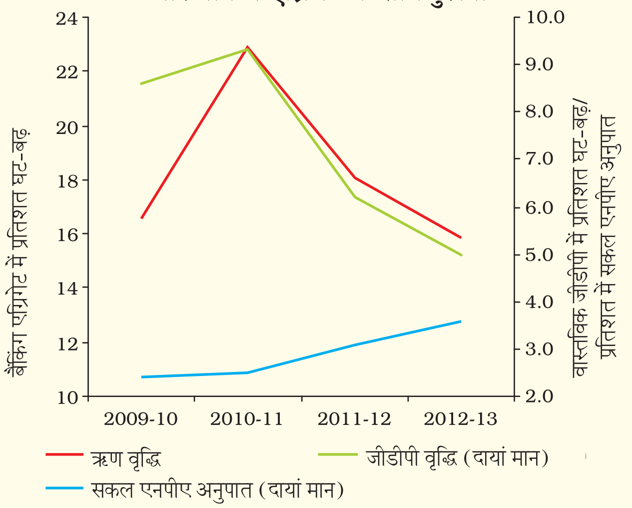

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था *पर सांख्यिकी* पुस्तिका, बैंकों के वार्षिक लेखे और ऑफ-*साइट विवरणी*।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	-4.2	4.3	-	4.5	-4.2	6.1	1.7	3.9	15.6	13.9	8.0	10.4
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	24.4	15.5	15.5	21.6	18.5	18.9	14.9	22.2	15.6	15.2	20.8	17.2
3. जमाराशियां	14.4	14.9	17.1	18.8	19.6	18.4	16.3	19.0	15.1	4.0	14.9	15.1
3.1 मांग जमाराशियां	-6.3	16.8	4.4	15.4	6.5	15.6	4.0	15.4	9.9	-7.8	-1.8	13.3
3.2 बचत बैंक जमाराशियां	12.1	14.4	19.1	19.3	16.3	14.9	19.9	20.5	5.6	2.9	13.1	15.0
3.3 सावधि जमाराशि	18.2	14.8	19.7	19.4	22.1	19.5	18.6	19.4	21.0	10.4	18.6	15.4
4. उधार	17.2	19.8	38.9	16.1	80.3	28.3	36.4	15.1	29.7	27.4	24.9	19.8
5. अन्य देयताएं एवं प्रावधान	-7.5	15.4	42.1	0.2	12.5	9.6	47.1	-1.0	26.9	-25.1	8.6	2.2
कुल देयताएं/ आस्तियां	14.1	15.3	21.1	17.5	21.3	18.6	21.0	17.2	19.8	5.7	15.8	15.1
1. भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष	-20.5	-0.2	-18.1	5.4	-7.9	-0.2	-20.8	7.1	14.2	-7.4	-18.5	0.4
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	40.7	38.0	15.6	57.9	80.4	52.6	6.5	59.2	13.7	10.7	32.4	37.5
3. निवेश	12.8	16.7	24.6	19.0	18.0	23.0	26.5	18.0	21.2	13.7	16.1	17.0
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां	16.5	13.5	32.0	17.8	21.5	23.8	35.4	16.1	23.0	21.5	19.8	15.0
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-65.1	-26.2	-78.8	-63.1	-65.0	-61.2	-97.6	-100.0	-100.0	-	-65.6	2.9
3.3 गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियां	-2.1	33.3	12.5	21.4	10.0	21.2	13.0	21.4	17.7	-3.8	5.2	24.1
4. ऋण और अग्रिम	17.3	15.4	21.2	18.3	24.6	17.3	20.1	18.6	17.6	14.7	18.1	15.9
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	25.7	20.8	8.2	7.8	14.7	-4.0	5.4	13.3	9.6	29.2	21.8	19.9
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि	17.8	16.9	28.4	28.8	33.3	25.9	25.4	30.7	19.7	14.7	19.3	18.5
4.3 सावधि ऋण	16.1	13.5	19.0	14.2	17.6	10.6	19.3	14.9	17.5	10.7	16.8	13.6
5. अचल आस्तियां	5.9	11.2	3.0	8.3	6.9	14.9	2.1	6.6	1.2	20.4	4.8	11.3
6. अन्य आस्तियां	14.9	2.8	67.5	-7.9	26.9	8.0	74.5	-9.9	26.9	-31.0	27.9	-9.5

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र

[4] भारतीय स्टेट बैंक समूह के मामले में, उच्च वृद्धि मुख्य रूप से 2012-13 की अंतिम तिमाही में हुई। चार्ट IV.2 के आकलन ऑफसाइट विवरणियों (घरेलू) से लिए गए ऋण के आंकड़ों पर आधारित हैं।

चार्ट IV.2: विभिन्न बैंक समूहों के सकल अग्रिमों में वृद्धि

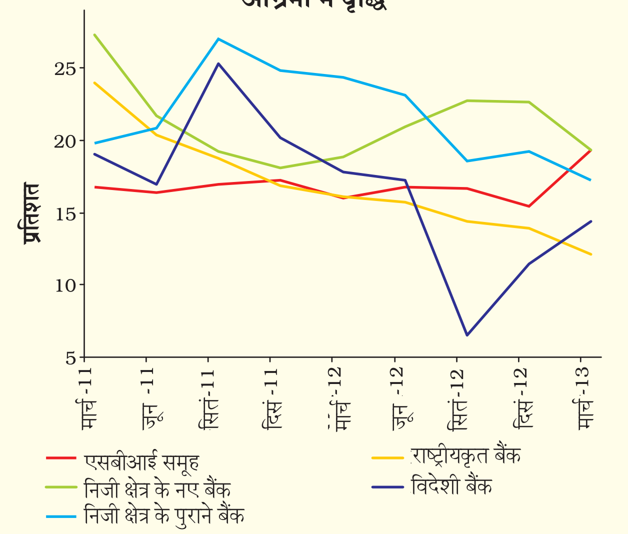

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां (घरेलू)

चार्ट IV.3: कासा की प्रवृत्ति

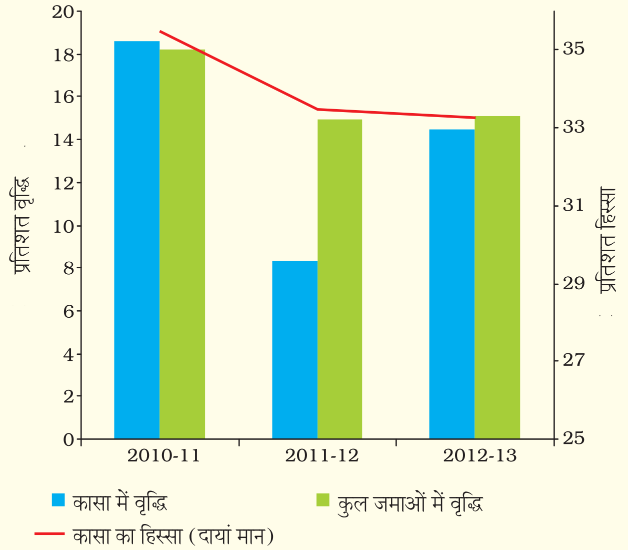

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

कासा जमाराशियों की वृद्धि में सुधार के कारण जमाराशियों की वृद्धि बनाए रखी जा सकी

4.4 हालांकि बैंकिंग क्षेत्र के तुलन-पत्र के आकार में कमी आयी, परंतु देयता पक्ष के सबसे बड़े घटक - जमाराशियों की वृद्धि में 2012-13 में सुधार देखा गया,ऐसा मुख्य रूप से चालू और बचत खाता (कासा) जमाराशियों में वृद्धि के कारण हुआ। नतीजतन, कासा जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में करीब 33 प्रतिशत बना रहा (चार्ट IV.3)।

निजी क्षेत्र के नए बैंकों में कासा जमाराशियों में पुनः वृद्धि हुई जो बचत जमा दर में आंशिक तौर पर बेहतर प्रतिस्पर्धा के कारण थी

4.5 निजी क्षेत्र के नए बैंकों में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में कासा जमाराशियों में वृद्धि स्पष्ट तौर पर देखी गई। वर्ष 2012-13 में, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की कासा जमाराशियों में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो सभी बैंक समूहों के बीच सबसे अधिक रही (चार्ट IV.4)। अंशतः, इसके लिए बचत जमा दर पर नियंत्रण हटाने के बाद, बचत जमाराशियों को आकर्षित करने के लिए बैंकों के बीच आई बेहतर प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार माना जा

चार्ट IV.4: बैंक समूहवार कासा की प्रवृत्ति

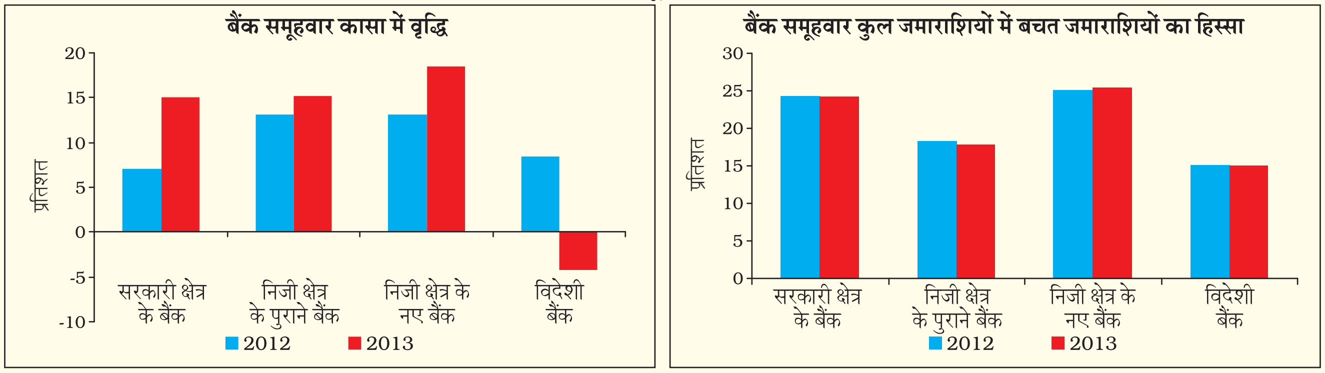

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सकता है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में कुल जमाराशियों का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा बचत जमाराशियों का है और वर्ष 2013 में यह सभी बैंक समूहों के बीच सबसे अधिक रहा (चार्ट IV.4)।

सकल आधार पर, बकाया ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा

4.6 बकाया आधार पर, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहकर लगभग 79 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा (चार्ट IV.5)। बैंक समूह स्तर पर, एसबीआई और विदेशी बैंक समूहों को छोड़कर सभी बड़े बैंक समूहों के बकाया ऋण-जमा अनुपात में थोड़ी कमी आयी (चार्ट IV.5) ।

4.7 दिसंबर 2012 के अंत में 102.9 प्रतिशत की तेजी को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में वर्ष 2012-13 के अधिकांश समय में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (चार्ट IV.6) ।

चार्ट IV.6: वृद्धिशील सी-डी और आई-डी अनुपात की प्रवृत्ति

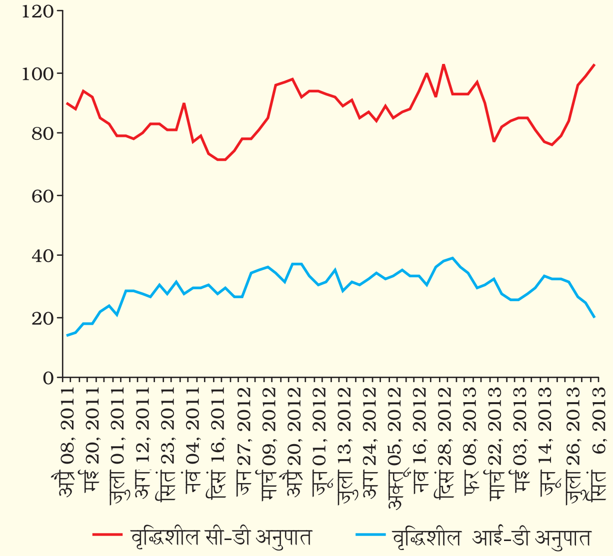

स्रोत: धारा 42(2) विवरणियां ।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि

4.8 2012-13 के दौरान अंतरराष्ट्रीय देयताओं और आस्तियों का पुराना रुझान पूरी तरह उलट रहा; हालांकि भारत में स्थित बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई जबकि इन बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां लगभग अपरिवर्तित रहीं (सारणी IV.2;

चार्ट IV.5: बैंक समूहवार बकाया सी-डी अनुपात की प्रवृत्ति

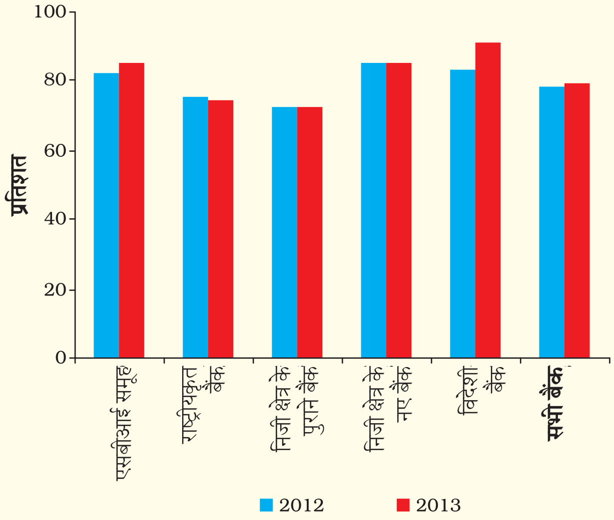

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

देयताओं के प्रकार	बकाया राशि (मार्च के अंत में)		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1. जमा और उधार	**4,472 (79.0)**	**5,274 (77.2)**	**18.2**	**17.9**
2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम	**56 (1.0)**	**58 (0.8)**	**23.0**	**3.1**
3. अन्य देयताएं	**1,133 (20.0)**	**1,503 (22.0)**	**-18.3**	**32.7**
जिसमें से:				
क) एडीआर / जीडीआर	271 (4.8)	393 (5.8)	-21.8	45.1
ख) अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	536 (9.5)	714 (10.4)	-26.8	33.2
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	326 (5.8)	396 (5.8)	5.8	21.4
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**5,661 (100.0)**	**6,835 (100.0)**	**8.6**	**20.7**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस(लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

सारणी IV.3: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1. ऋण और निवेश	**3,410 (97.3)**	**3,453 (97.5)**	**22.3**	**1.3**
जिसमें से:				
क) अनिवासियों को उधार *	156 (4.4)	163 (4.6)	8.1	4.9
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार**	1,652 (47.2)	1,740 (49.1)	17.9	5.3
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	725 (20.7)	791 (22.3)	18.3	9.1
घ) नोस्ट्रो शेष@	865 (24.7)	745 (21.0)	38.7	-13.8
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	**0.0 (0.0)**	**5.2 (0.1)**	**-100.0**	**-**
3. अन्य आस्तियाँ @@	**94 (2.7)**	**85 (2.4)**	**2.9**	**-9.5**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**3,504 (100.0)**	**3,544 (100.0)**	**21.6**	**1.1**

* अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा (एफसी) ऋण को शामिल किया गया है।

** एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में से दिए गए उधार, विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी), भारत स्थित बैंकों को एफसी उधार तथा भारत स्थित बैंकों में जमा राशियां आदि शामिल हैं।

@ विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों की मीयादी जमाराशियों में शेष शामिल हैं।

@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस(लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

IV.3)। भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित दावों के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है कि 2012-13 में निजी गैर-बैंकिंग क्षेत्र की ओर रुझान स्पष्ट रूप से था जो हाल के वर्षों में वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है (सारणी IV.4)। यह रुझान अमेरिका और उन्नत यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिटेन और जर्मनी से दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं जैसे हांगकांग और सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात की ओर भी स्पष्ट रूप से शिफ्ट होता दिखता है (सारणी IV.5)। यह आंशिक रूप से वैश्विक वित्तीय और सरकारी ऋण संकट के फलस्वरूप इस अवधि में सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त अनिश्चित आर्थिक वातावरण का नतीजा हो सकता है।

सारणी IV.4: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,809 (100.0)**	**3,312 (100.0)**	**14.0**	**17.9**
क) परिपक्वता - वार				
1. अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,832 (65.2)	2,153 (65.0)	19.0	17.5
2. दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	924 (32.9)	1,100 (33.2)	5.9	19.1
3. अनाबंटित	54 (1.9)	59 (1.8)	1.7	10.1
ख) क्षेत्र वार				
1. बैंक	1,286 (45.8)	1,383 (41.8)	17.8	7.6
2. बैंकेतर सार्वजनिक	19 (0.7)	31 (0.9)	114.1	66.2
3. बैंकेतर निजी	1,505 (53.6)	1,898 (57.3)	10.3	26.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक की रिपोर्टिंग शाखाओं से उपलब्ध न कराई गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3. 'बैंक' क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित राज्य/ केंद्र सरकारों की कम-से- कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्र सरकार और उनके विभाग शामिल हैं और तदनुसार, बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं 'बैंकेतर निजी क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं।
5. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।

आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता स्वरूप

अल्पावधि परिपक्वता बकेट में आस्तियों और देयताओं के बीच अंतर सबसे अधिक रहा

4.9 मुख्य रूप से अल्पावधि परिपक्वता वाली[5] जमाराशियों द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालिक आधारभूत ढांचागत कर्ज के प्रति इस क्षेत्र के बढ़ते एक्सपोजर को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिपक्वता अंतर को प्रायः चिंता के रूप में देखा गया है। इस तरह

[5] *देखें भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट- 2011-12।*

सारणी IV.5: भारत को छोड़कर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(₹ बिलियन)

देश	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	2012	2013	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,809 (100.0)**	**3,312 (100.0)**	**14.0**	**17.9**
जिसमें से:				
1. अमरीका	643 (22.9)	676 (20.4)	17.2	5.2
2. यूनाइटेड किंगडम	364 (13.0)	431 (13.0)	6.0	18.3
3. हांगकांग	220 (7.8)	266 (8.0)	19.5	20.9
4. सिंगापुर	216 (7.7)	279 (8.4)	16.3	29.4
5. संयुक्त अरब अमीरात	221 (7.9)	277 (8.4)	42.8	25.1
6. जर्मनी	118 (4.2)	136 (4.1)	-16.6	15.1

टिप्पणी: 1. कुल संख्या का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: सीबीएस (समेकित बैंकिंग सांख्यिकी) विवरणों के आधार पर - देश का तत्काल जोखिम आधार।

का अंतर बैंक की चलनिधि, आय और कभी-कभी ऋण-शोधन क्षमता पर दबाव डाल सकता है।

4.10 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं और आस्तियों के परिपक्वता स्वरूप के समग्र विश्लेषण से पता चला कि 1 वर्ष तक के सबसे कम परिपक्वता वाले बकेट में धनात्मक अंतराल (देयताओं- आस्तियों) है। यह अन्य परिपक्वता बकेट की तुलना में सबसे अधिक है। यह अल्पकालिक देयताओं पर अधिक निर्भरता की ओर संकेत करता है जो अल्पावधि आस्तियों के तदनुरूपी सृजन से काफी अधिक है। यह अंतराल शेष तीन परिपक्वता बकेट अर्थात, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 साल और 5 साल से अधिक के लिए आम तौर पर ऋणात्मक पाया गया। यह मध्यावधि/ दीर्घावधि आस्तियों के अधिक से अधिक सृजन की ओर संकेत करता है जो मध्यावधि/ दीर्घावधि देयताओं के अनुपात से काफी अधिक है (सारणी IV.6; IV.7)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्रेतर परिचालन

वर्ष 2012-13 में बैंकों के तुलन-पत्रेतर परिचालन में मंदी

4.11 वर्ष 2012-13 में न सिर्फ तुलन-पत्र में बल्कि तुलन-पत्रेतर मदों में भी मंदी का असर दिखाई दिया हालांकि तुलन-पत्रेतर मदों में

सारणी IV.6: चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	49.6	33.9	48.7	46.0	48.1	48.5	48.9	45.1	61.9	62.0	50.0	35.6
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	25.3	31.3	30.0	27.4	39.2	37.5	26.6	23.7	29.8	28.9	26.3	30.9
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	8.5	15.9	5.7	9.1	6.9	7.4	5.2	9.7	8.3	9.0	8.0	15.1
घ) 5 वर्ष से अधिक	16.6	18.9	15.7	17.5	5.8	6.6	19.3	21.5	0.1	0.1	15.7	18.4
II. उधार राशियां												
क) 1 वर्ष तक	45.4	55.6	50.3	45.9	63.7	66.2	49.2	44.0	84.5	89.5	52.6	57.0
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	12.2	11.8	11.8	14.4	13.4	14.5	11.7	14.4	9.2	6.0	11.7	11.8
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	15.2	9.8	12.5	14.0	7.8	8.6	12.9	14.5	2.7	2.7	12.5	9.9
घ) 5 वर्ष से अधिक	27.2	22.9	25.4	25.7	15.1	10.6	26.2	27.0	3.5	1.8	23.2	21.3
III. ऋण और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	34.3	23.8	35.2	35.0	44.0	45.8	32.4	31.7	67.2	65.1	35.9	25.8
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	37.4	49.8	37.1	36.8	36.1	34.2	37.4	37.7	15.5	17.7	36.3	47.8
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	11.0	8.2	11.3	11.7	9.1	9.6	12.0	12.3	4.8	6.3	10.8	8.5
घ) 5 वर्ष से अधिक	17.3	18.1	16.4	16.5	10.8	10.4	18.2	18.4	12.5	10.8	17.0	17.8
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	20.1	16.6	42.6	41.8	30.3	38.5	45.9	42.7	76.7	77.9	30.4	23.1
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	12.6	17.2	17.3	18.2	12.2	16.3	18.6	18.8	12.9	11.0	13.7	17.1
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14.2	20.9	9.1	9.9	13.0	11.1	8.1	9.5	5.2	3.5	12.2	18.5
घ) 5 वर्ष से अधिक	53.1	45.2	31.0	30.1	44.4	34.1	27.4	29.0	5.2	7.5	43.6	41.3

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

चार्ट IV.7: विभिन्न परिपक्वता बकेट की देयताओं और आस्तियों के अनुपात के बीच अंतर

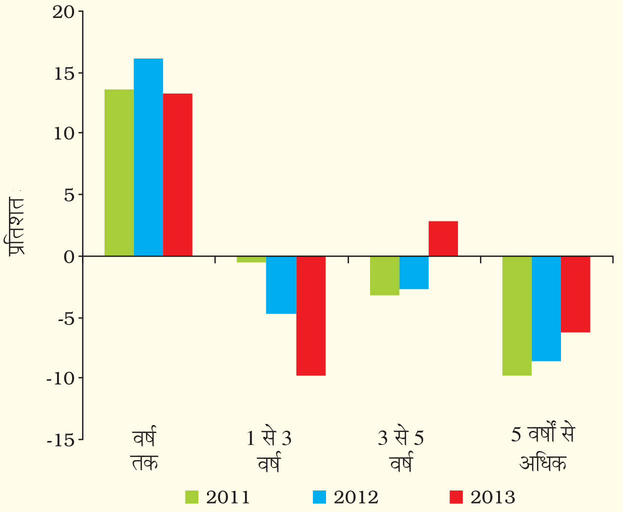

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

मंदी का असर अधिक स्पष्ट रहा। हाल में इन दोनों मदों में एक साथ हुई वृद्धि यह संकेत देती है कि इन दोनों के बीच एक निश्चित पूरकता है (परिशिष्ट सारणी IV.2; चार्ट IV.8)।

चार्ट IV.8: तुलन पत्र और तुलन पत्रेतर लेनदेनों में वृद्धि

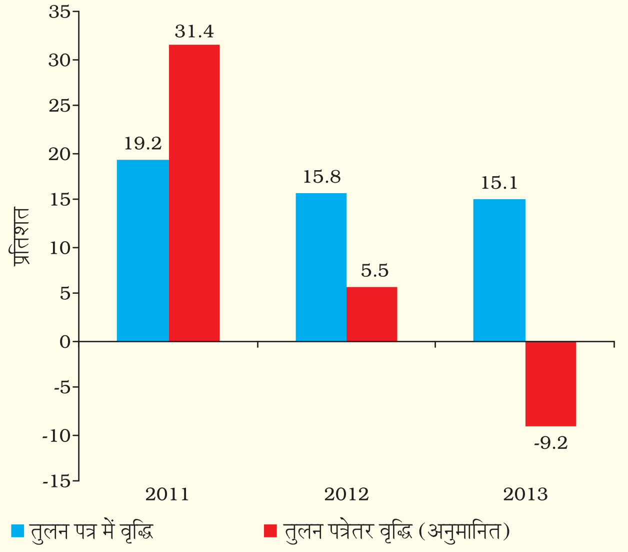

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

कम ऋण वितरण के साथ मुनाफे में धीमी वृद्धि ने ब्याज आय को प्रभावित किया

4.12 2012-13 में ऋण वृद्धि में गिरावट आने के कारण ब्याज आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी अवधि में ब्याज दरों में गिरावट आनी शुरू हो गई जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान ये अधिक हो गई थीं (सारणी IV.7; चार्ट IV.9)। ब्याज व्यय में भी वर्ष के दौरान धीमी गति से बढ़ोतरी हुई लेकिन यह बढ़ोतरी अर्जित ब्याज से अधिक थी जिसके कारण बैंकों के परिचालन और निवल लाभ दोनों की वृद्धि पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा।

पिछली प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2012-13 में आस्तियों पर प्रतिलाभ में और अधिक संकुचन हुआ।

4.13 लाभप्रदता के संकेतक के तौर पर सामान्यत: प्रयुक्त होने वाले आस्तियों पर प्रतिलाभ में 2012-13 में लगभग 5 आधार अंक की और गिरावट आयी (सारणी IV.8)। इस गिरावट को सामान्य

सारणी IV.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	2011-12		2012-13	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. आय	**7,416**	**29.8**	**8,614**	**16.2**
क) ब्याज आय	6,553	33.4	7,636	16.5
ख) अन्य आय	863	8.1	978	13.3
2. व्यय	**6,600**	**31.8**	**7,702**	**16.7**
क) व्यय किया गया ब्याज	4,304	44.0	5,138	19.4
ख) परिचालन व्यय	1,376	11.7	1,566	13.8
जिसमें से: वेतन बिल	780	7.3	873	11.9
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	920	16.8	998	8.5
3. परिचालन लाभ	**1,737**	**16.5**	**1,910**	**10.0**
4. निवल लाभ	**817**	**16.1**	**912**	**11.6**
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	**2,249**	**16.9**	**2,498**	**11.1**
निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के प्रतिशत रूप में एनआईआई)	**2.9**		**2.8**	

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमा और उधार दरों की प्रवृत्ति

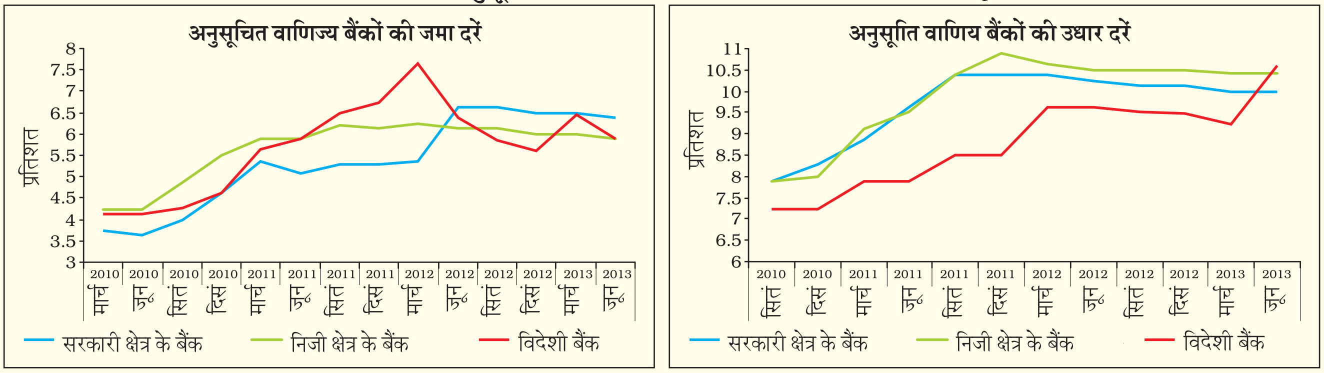

टिप्पणी: 1. दरों को न्यूनतम और अधिकतम दरों के औसत की मध्य बिन्दु के रूप में लिया गया है।
2. जमा दर से तात्पर्य 1 वर्ष तक की जमाराशियों पर प्रभारित दरों से है क्योंकि इन जमाओं का हिस्सा सभी बैंक समूहों की कुल जमाराशियों में सबसे अधिक है।

तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों विशेष तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

नए निजी/विदेशी बैंकों ने अपने परिचालन व्ययों की वृद्धि में कमी लाकर लाभप्रदता में सुधार किया

4.14 निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विदेशी बैंकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई समूह की तुलना में 2012-13 में आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि की सूचना दी। 2012-13 में नए निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों के लाभ की वृद्धि में तीव्र गिरावट नहीं दिखाई दी, जैसाकि राष्ट्रीयकृत बैंकों और एसबीआई समूह के मामले में ऐसा हुआ। हालांकि वर्ष के दौरान नए निजी/विदेशी बैंकों की ब्याज आय में कम वृद्धि हुई, पर वे अपने परिचालन व्ययों, विशेषकर वेतन बिल की वृद्धि में कटौती कर अपने लाभ वृद्धि को बरकरार रख सके (चार्ट IV.10)।

2012-13 में निवल ब्याज मार्जिन तथा स्प्रेड दोनों कम हुए

4.15 हाल के वर्षों की प्रवृत्ति को देखते हुए, निवल ब्याज मार्जिन और स्प्रेड (प्रतिफल और लागत निधि के बीच का अंतर) दोनों में समग्र स्तर पर गिरावट आई जिससे पता चलता है कि अनुसूचित

सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल-बैंक समूह वार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह/वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
	1	2	3	4	5
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**0.88**	**0.78**	**15.33**	**13.24**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक *	0.88	0.74	15.05	12.34
	1.2 एसबीआई समूह	0.89	0.88	16.00	15.29
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**1.53**	**1.63**	**15.25**	**16.46**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.20	1.26	15.18	16.22
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.63	1.74	15.27	16.51
3	**विदेशी बैंक**	**1.76**	**1.94**	**10.79**	**11.52**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.08**	**1.03**	**14.60**	**13.84**

टिप्पणी: 1. आस्तियों पर प्रतिफल = निवल लाभ/औसतन कुल आस्तियां
2. इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ/ औसतन कुल इक्विटी
3. * राष्ट्रीकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि.शामिल है।

स्रोत : संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

चार्ट IV.10: आय और व्यय के चयनित मदों में वृद्धि

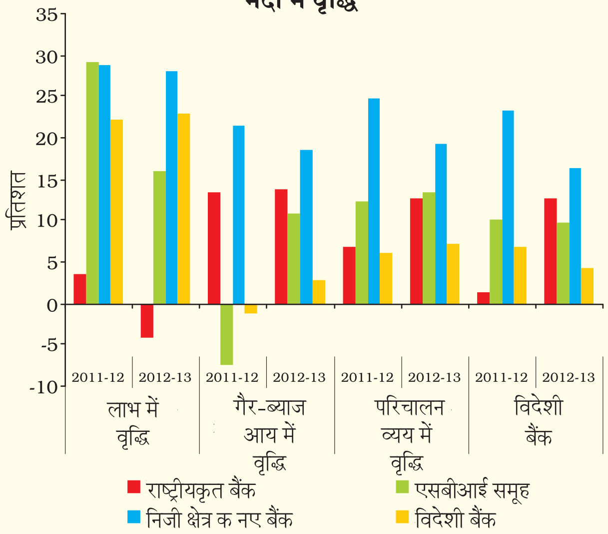

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

सारणी IV.9: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह /वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-5)
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**							
	2011-12	**6.36**	**2.80**	**6.06**	**10.31**	**7.54**	**9.52**	**3.46**
	2012-13	**6.63**	**2.45**	**6.27**	**10.08**	**7.60**	**9.38**	**3.11**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*							
	2011-12	6.51	2.77	6.22	10.32	7.43	9.49	3.27
	2012-13	6.74	2.37	6.39	10.16	7.42	9.36	2.97
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2011-12	5.97	2.85	5.66	10.27	7.80	9.60	3.94
	2012-13	6.37	2.58	5.96	9.90	8.08	9.42	3.46
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**							
	2011-12	**6.43**	**2.92**	**5.84**	**11.06**	**7.26**	**9.73**	**3.89**
	2012-13	**6.72**	**3.33**	**6.12**	**11.52**	**7.28**	**10.02**	**3.91**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2011-12	7.24	4.34	7.10	11.98	7.37	10.47	3.37
	2012-13	7.46	4.33	7.27	12.15	7.49	10.62	3.35
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2011-12	6.14	2.81	5.45	10.77	7.23	9.51	4.06
	2012-13	6.45	3.24	5.77	11.33	7.22	9.85	4.08
3	**विदेशी बैंक**							
	2011-12	**4.34**	**2.78**	**3.88**	**9.61**	**8.02**	**8.87**	**4.99**
	2012-13	**4.67**	**2.78**	**4.05**	**9.55**	**8.13**	**8.89**	**4.84**
4	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**							
	2011-12	**6.28**	**2.83**	**5.90**	**10.42**	**7.52**	**9.53**	**3.63**
	2012-13	**6.57**	**2.76**	**6.12**	**10.33**	**7.57**	**9.49**	**3.36**

टिप्पणी:
- जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत।
- उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के उधारों का औसत।
- निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज +उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
- अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत।
- निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत।
- निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।

*आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्रों से परिकलित।

वाणिज्य बैंकों की परिचालन दक्षता में कुछ सुधार आया है (सारणी IV.7; IV.9)। मानक लेखांकन मानदंडों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि हाल के दशकों में बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार हुआ है (बॉक्स IV.1) ।

बॉक्स IV.1 :
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में दक्षता विश्लेषण- एक अनुपात दृष्टिकोण

बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में निरंतर सुधार आवश्यक है क्योंकि वे निम्नानुसार योगदान देते हैं - (क) उच्चतर आर्थिक विकास - एक कार्यकुशल बैंकिंग क्षेत्र, संसाधनों को जुटा करके तथा आबंटन के अपने बुनियादी कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है (मोहन, 2005); (ख) जोखिम का न्यूनीकरण - बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक दक्ष होगी वह उतनी ही कुशलता के साथ जोखिम आघातों को सहन कर सकेगी और इससे ऊबर सकेगी। इसकी कड़ी अनिवार्य रूप से अधिक से अधिक पूंजी बफर बनाकर, दक्षता में सुधार के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता से जुड़ी है। वास्तव में, अध्ययन से पता चला है कि लागत दक्षता तथा किसी बैंक की विफलता के जोखिम (पॉडपियरा और पॉडपियरा, 2005) के बीच एक नकारात्मक और महत्त्वपूर्ण संबंध है; (ग) बेहतर वित्तीय समावेशन - बैंकिंग प्रणाली जितना अधिक दक्ष होगी उतनी ही कुशलता के साथ यह वित्तीय समावेशन के लिए योगदान दे सकेगी, विशेष रूप से यह बैंकिंग सेवाओं की सुपुर्दगी को किफायती बनाएगी और इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बैंकिंग सेवाओं तक अधिक पहुंच से इसके उपयोग में सुधार आएगा (चक्रवर्ती, 2013)।

सैद्धांतिक रूप से, दक्षता और उत्पादकता/लाभप्रदता के बीच एक बारीक सा अंतर है। जबकि, उपलब्ध इनपुट और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादकता के लाभ अधिकतम संभव आउटपुट प्राप्त करने की बैंक की क्षमता का परिचायक हैं, वहीं दक्षता सामान्य अर्थ में उद्योग जगत के अग्रणी के साथ तुलना करके बैंक के कार्य-निष्पादन को मापती है (भारतीय रिजर्व बैंक, 2008)। अनुभवजन्य तौर,

(जारी...)

(...समाप्त)

बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता को मापने के दो तरीके हैं: (क) उत्पादकता/लाभप्रदता के मानक लेखांकन उपाय के माध्यम से और (ख) डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक के माध्यम से जिसमें संसाधनों का इष्टतम स्तर पर उपयोग करने वाले सबसे अच्छे फ्रंटियर का आकलन किया जाता है, और किसी खास बैंक की दक्षता को उस फ्रंटियर के सापेक्ष में मापा जाता है।

लागत-आय अनुपात, निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिलाभ: दक्षता/लाभप्रदता के विश्लेषण के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त लेखांकन उपाय/अनुपात इस प्रकार हैं : लागत-आय अनुपात में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा राजस्व/आय की एक इकाई को जुटाने की लागत को कवर किया जाता है जो लागत दक्षता को परिलक्षित करता है। यह अनुपात जितना कम होगा, बैंकिंग क्षेत्र उतना ही कुशल होगा। निवल ब्याज मार्जिन में, ऋण और निवेश परिचालनों के माध्यम से अपनी जमाराशियों और उधार ली गई निधियों को नियोजित कर आय सृजन करने में इस क्षेत्र की मध्यस्थता संबंधी दक्षता को, कवर किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होगा, बैंकिंग क्षेत्र उतना ही अधिक कुशल होगा। आस्तियों पर प्रतिलाभ में, बैंकों को अपनी आस्तियों को नियोजित करने की दक्षता को कवर किया जाता है। यह अनुपात जितना ही अधिक होगा, बैंकिंग क्षेत्र का संचालन उतना ही अधिक कुशल होगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, लागत-आय अनुपात के माध्यम से आकलित लागत दक्षता के अनुसार भारत, चीन को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और अन्य ब्रिक्स के देशों से ऊपर है। निवल ब्याज मार्जिन के माध्यम से प्राप्त दक्षता के संदर्भ में भारत अन्य ब्रिक्स देशों के समतुल्य है लेकिन अभी भी सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। आस्तियों पर प्रतिलाभ के माध्यम से प्राप्त लाभप्रदता के संदर्भ में इसकी तुलना अन्य ब्रिक्स देशों और उन्नत देशों से की जा सकती है (सारणी)।

1990 के दशक से आरंभ लेकर शुरू किए गए बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का प्रमुख उद्देश्य बैंकों की परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार रहा है। लागत-आय अनुपात, निवल ब्याज मार्जिन और आस्तियों पर प्रतिलाभ के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान प्रणाली में कुल मिलाकर लागत-आय अनुपात और निवल ब्याज मार्जिन में कमी आयी है और आस्तियों पर प्रतिलाभ में भी सुधार आया है, हालांकि इसमें कुछ उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। बासेल II के मानदण्डों के अनुसार, बैंकों को 40 प्रतिशत का लागत-आय अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जबकि बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ 1 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए (भारतीय रिज़र्व बैंक, 2008)। 2000 के दशक में, भारत का कार्य-निष्पादन इन दो मानकों के तुलनीय है (चार्ट)। इस प्रकार, मानक लेखा उपाय/अनुपात यह दर्शाते हैं कि हाल के दशकों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की प्रवृत्ति रही है।

सारणी: चुनिंदा देशों में लाभप्रदता और क्षमता के संकेतक

(प्रतिशत)

देश	आय की तुलना में लागत	एनआईएम	आरओए
चुनिंदा उन्नत देश			
यूएसए	60.59	3.64	0.83
जापान	61.65	1.01	0.28
यूके	67.79	1.09	0.16
डेनमार्क	70.32	1.12	0.07
फ्रांस	75.37	0.90	0.11
जर्मनी	83.62	0.78	0.02
इटली	89.63	1.37	-1.10
ब्रिक्स			
चीन	38.48	2.74	0.77
भारत	*44.53*	*3.02*	*0.95*
ब्राजील	57.28	4.97	1.21
दक्षिण अफ्रीका	57.34	2.76	1.10
रूस	90.03	3.93	1.27

टिप्पणी: देशों की रैंकिंग, आय की तुलना में लागत का अनुपात के आधार पर की गई है। डेटा 2011 के हैं। भारत का डेटा वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है ताकि वह परिभाषा के संदर्भ में अन्य देशों के साथ तुलनीय हो।

स्रोत: बैंकस्कोप, फाइनेंशियल स्ट्रकचर डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक।

चार्ट: क्षमता दर्शाते लेखांकन मानदंडों की प्रवृत्तियां

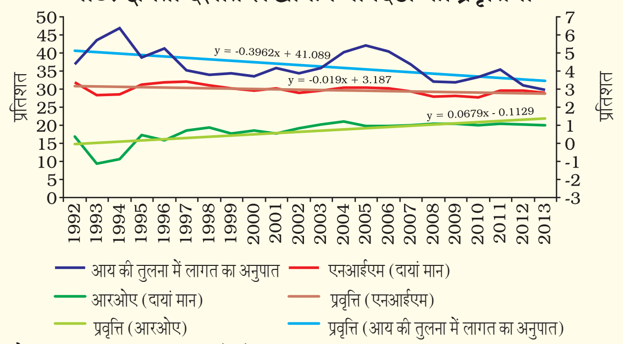

स्रोत: 1. एनआईएम की परिभाषा है औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय। आरओए की परिभाषा है औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ और लागत आय अनुपात की परिभाषा है कुल आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन लागत (इसमें प्रावधान और आकस्मिक व्यय भी शामिल हैं)।
2. प्रवृत्ति का तात्पर्य आनुक्रमिक समय प्रवृत्ति से है।

टिप्पणी: भारत में बैंकों की सांख्यिकीय सारणी, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, विभिन्न अंक।

संदर्भ : चक्रवर्ती के.सी (2013), ''प्रोडक्टीविटी ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग इन दि पोस्ट रिफार्म पीरियड-एक्सपीरियेंस, इसूज और फ्यूचर चेलेंजेज'' एड्रेस एट दि एफआईबीएसी, अगस्त।

मोहन, राकेश (2005) ''इंडियन इकोनॉमी इन ग्लोबल सेटिंग'', *आरबीआई बुलेटिन,* अक्तूबर।

पॉडपियरा, ए और जे पॉडपियरा (2005) डिटियोरेटिंग कॉस्ट इफिसियंशी इन कमर्शियल बैंक्स सिग्नल्स एन इनक्रीजिंग रिस्क ऑफ फेल्यूर'' सीएनबी वर्किंग पेपर सीरीज, दिसंबर।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (2008), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2006-08, मुंबई।

4.16 मानक लेखांकन मानंदडों के अलावा, बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता को तय करने की एक दूसरी सामान्य रूप से प्रयुक्त तकनीक डेटा इन्वेलपमेंट एनेलिसिस है। इस तकनीक को भी प्रयोग करने पर पाए गए अनुमान के अनुसार, हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की एक प्रवृत्ति दिखी है (बॉक्स IV.2)।

बॉक्स IV.2:
डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक का प्रयोग कर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता का विश्लेषण

बॉक्स IV.1 में दिखाए गए के अनुसार, मानक लेखांकन मानदंडों का प्रयोग कर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार की प्रवृत्ति की पुष्टि, डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक का प्रयोग कर प्राप्त किए गए दक्षता अनुमानों से भी की जा सकती है (चार्ट)। यहां डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक (डीईए) "मध्यस्थता" दृष्टिकोण पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, बैंकों को वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाएं माना जाता है जो निर्धारित आउटपुट[6] के लिए एक निश्चित इनपुट का प्रयोग करती हैं। तदनुसार, इनपुट को जमाराशि और उधार तथा कुल लागत (ब्याज और परिचालनगत व्यय) के रूप में लिया गया है ताकि अर्जक आस्तियों (ऋण और निवेश का जोड़ शामिल है) के सृजन को आउटपुट के रूप में माना जा सके। विश्लेषण की अवधि वर्ष 2000 से 2013 तक की है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और बैंकिंग क्षेत्र[7] की गतिविधियों का उच्च विकास चरण और मंदी का वर्तमान चरण शामिल किया गया है। डेटा इन्वेलपमेंट तकनीक एक इनपुट उन्मुख मॉडल का अनुकरण करती है जो लागत में कमी की सीमा को तय करती है क्योंकि यह निर्धारित आउटपुट[8] के स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से सरकारी क्षेत्र के बैंकों का औसत दक्षता स्कोर, विचाराधीन अवधि के अधिकांश भाग में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक रहा। हालांकि, वे 2010 के बाद निजी क्षेत्र के बैंकों के स्कोर से पीछे हो गए, इस अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संवृद्धि और लाभप्रदता में गिरावट देखी गई। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में जहाँ तक दक्षता स्तर की बात है, सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उतार-चढ़ाव बहुत कम रहा (सारणी)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई समूह ने आम तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अधिक दक्षता दिखाई। हालांकि, वर्ष 2010 के बाद इन दोनों बैंक समूह के औसत दक्षता स्तरों में अभिरूपता के संकेत थे (चार्ट)।

चार्ट: डीईए का उपयोग करते हुए दक्षता की प्रवृत्ति

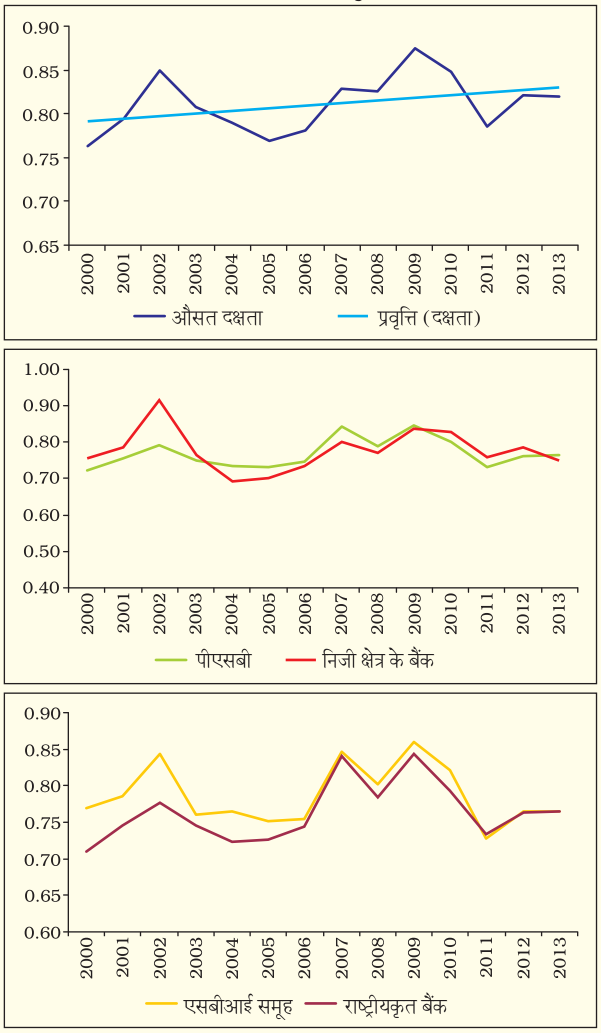

स्रोत: भारत में बैंकों की सांख्यिकीय सारणी, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट से लिए गए डेटा का उपयोग कर परिकलित दक्षता स्कोर, विविध मुद्दे।

संदर्भ:

बर्गर, ऐलन एन. एंड डेविड हंफ्रे (1997), 'इफिशिएंसी ऑफ फायनेंशियल इंस्टिट्यूशंसः इंटरनैशनल सर्वे एंड डाइरेक्शन्स फॉर फ्यूचर रिसर्च', *यूरोपियन जर्नल ऑफ आपरेशनल रिसर्च,* 98(2)।

दास, अभिमान, अशोक नाग एंड सुभाष सी. रे (2005), ''लिब्रलाइजेशन, ओनरशिप एंड इफिशिएंसी इन इंडियन बैंकिंगः ए नॉनपैरामेट्रिक एनैलसिस'', इकोनॉमिक एंड पालिटिकल वीकली, 40(12)।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2008), मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट - 2006-08, मुंबई।

सारणी: दक्षता स्तर में घट-बढ़ की प्रवृत्ति

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
सरकारी क्षेत्र के बैंकों में घट-बढ़ (%) का सहगुणांक													
5.9	5.8	4.9	8.0	7.8	6.8	4.2	2.7	1.9	2.6	3.0	2.4	2.0	2.2
निजी क्षेत्र के बैंकों में घट-बढ़ (%) का सहगुणांक													
18.0	10.4	59.6	14.0	12.3	8.7	10.2	7.3	7.6	6.1	6.1	10.0	5.6	7.3

[6] देखें बर्गर एंड हंफ्री (1997) और दास एट एल (2005)

[7] विभिन्न समयों में सेक्टोरल दक्षता की तुलनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, इस विश्लेषण के लिए विचारित सैम्पल में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया गया है जो इस अवधि के दौरान परिचालन में थे।

[8] इसलिए यदि दक्षता स्कोर 0.80 है, तब उपलब्ध इनपुट-आउटपुट संयोजन और प्रौद्योगिकी को देखते हुए, आउटपुट के समान स्तर के उत्पादन के लिए 20 प्रतिशत लागत कम की जा सकती हैं।

सारणी IV.10: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

मद/ बैंक समूह	बासेल I		बासेल II	
	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**11.88**	**11.31**	**13.23**	**12.38**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	11.84	11.39	13.03	12.26
भारतीय स्टेट बैंक समूह	11.97	11.14	13.70	12.67
निजी क्षेत्र के बैंक	**14.47**	**15.10**	**16.21**	**16.84**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	12.47	12.33	14.12	13.73
निजी क्षेत्र के नए बैंक	14.90	15.71	16.66	17.52
विदेशी बैंक	**17.30**	**18.76**	**16.75**	**17.87**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**12.94**	**12.77**	**14.24**	**13.88**

टिप्पणी: *: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4. सुदृढ़ता संकेतक

सीआरएआर, बासेल I और II दोनों के तहत निर्धारित मानदंड से अधिक रहा

4.17 पूर्व रुझान की तरह, 2012-13 में जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) प्रणाली और बैंक समूह दोनों के स्तर पर निर्धारित 9 प्रतिशत से ऊपर बना रहा, लेकिन इसमें गिरावट का रुख देखा गया (सारणी IV.10)। बासेल II के अंतर्गत कोर सीआरएआर (टियर-I) में भी थोड़ी गिरावट आई (सारणी IV.11)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजीगत स्थिति में गिरावट के कारण समग्र स्तर पर पूंजीगत स्थिति में गिरावट रही।

सारणी IV.11: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च के अंत में)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2012	2013	2012	2013
क. पूंजी निधियां (i + ii)	**7,810**	**8,906**	**7,780**	**8,879**
i) टियर I पूंजी	5,686	6,595	5,672	6,580
ii) टियर II पूंजी	2,124	2,311	2,109	2,299
ख. जोखिम भारित आस्तियां	**60,376**	**69,742**	**54,621**	**63,969**
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	**12.94**	**12.77**	**14.24**	**13.88**
जिसमें से: टियर I	9.42	9.46	10.38	10.29
टियर II	3.52	3.31	3.86	3.59

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4.18 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने के गंभीर राजकोषीय परिणामों को देखते हुए, इन बैंकों की पूंजीगत स्थिति में गिरावट चिंता का कारण है (सारणी IV.12)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सांविधिक स्तर से ऊपर बने रहे। चूँकि वे बासेल III के उन्नत ढांचे में अंतरण कर रहे हैं, अतः उनकी पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता (सामान्य इक्विटी) दोनों को बेहतर बनाने की आवश्यकता होगी, साथ ही अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करना होगा और सार्वजनिक स्वामित्व के स्तर को भी बनाए रखना होगा।

अनर्जक आस्तियां

अनर्जक आस्तियां बैंकिंग क्षेत्र के लिए दबाव का कारण बनी रहीं

4.19 मार्च 2013 के अंत में समग्र स्तर पर सकल एनपीए अनुपात 3.6 प्रतिशत था, जो मार्च 2012 के अंत के 3.1 प्रतिशत से अधिक था (सारणी IV.13)। स्टेट बैंक समूह की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट सबसे स्पष्ट दिखी, जिसका एनपीए अनुपात मार्च 2013 के अंत में 5 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया। मार्च 2013 के अंत में लगभग 3.6 प्रतिशत के सकल एनपीए अनुपात के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान स्टेट बैंक समूह के ठीक बाद था।

सारणी IV.12: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण पर व्यय की गई राशि

वर्ष	पुनर्पूंजीकरण राशि (बिलियन ₹ में)
2000-01	-
2001-02	13
2002-03	8
2003-04	-
2004-05	-
2005-06	5
2006-07	-
2007-08	100
2008-09	19
2009-10	12
2010-11	201
2011-12	120
2012-13	125
2013-14	140

- उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: वित्त मंत्रालय, यूनियन बजट के दस्तावेज और मुद्रा एवं वित्त की रिपोर्ट, 2006-08 से संकलित।

सारणी IV.13: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूहवार

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल एनपीए								
2011-12 के लिए अंतिम शेष	**1,178**	696	482	**187**	42	145	**62**	**1,429**
2012-13 का प्रारंभिक शेष	**1,178**	696	482	**187**	42	145	**62**	**1,429**
2012-13 के दौरान जोड़	**1,198**	772	425	**128**	41	87	**41**	**1,368**
2012-13 के दौरान वसूली	**648**	429	219	**63**	30	33	**24**	**736**
2012-13 के दौरान बट्टा खाता डाले गए	**78**	17	60	**42**	1	40	**0**	**120**
2012-13 का अंतिम शेष	**1,650**	1,022	627	**210**	52	158	**79**	**1,940**
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए								
2011-12	**3.3**	**2.8**	**4.6**	**2.1**	**1.8**	**2.2**	**2.6**	**3.1**
2012-13	**4.1**	**3.6**	**5.0**	**2.0**	**1.9**	**2.0**	**2.9**	**3.6**
निवल एनपीए								
2011-12 का अंतिम शेष	**593**	391	202	**44**	13	30	**14**	**652**
2012-13 का अंतिम शेष	**900**	619	281	**59**	20	39	**26**	**986**
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप निवल एनपीए								
2011-12	**1.5**	1.4	1.8	**0.5**	0.6	0.4	**0.6**	**1.3**
2012-13	**2.0**	2.0	2.0	**0.5**	0.8	0.4	**1.0**	**1.7**

टिप्पणी: 1.* : आईडीबीआई बैंक लि. सहित।
2.**: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से सकल अनर्जक आस्तियां तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिमों को लेकर गणना की गई है।
स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

4.20 "संदिग्ध" कर्ज आस्तियों के अनुपात में वृद्धि के कारण अनर्जक आस्तियों के भीतर भी गंभीर गिरावट के चिन्ह देखे गए (सारणी IV .14)। कर्ज आस्तियों के "संदिग्ध" श्रेणी में अंतरण की सबसे अधिक घटनाएं स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुईं।

सारणी IV.14: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**2012**	**38,255**	**97.0**	**623**	**1.6**	**490**	**1.2**	**60**	**0.1**
		2013	**43,957**	**96.4**	**815**	**1.8**	**761**	**1.7**	**68**	**0.1**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक **	2012	26,909	**97.5**	402	**1.5**	268	**1.0**	21	**0.1**
		2013	30,396	**96.8**	558	**1.8**	424	**1.3**	35	**0.1**
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2012	11,345	**95.9**	221	**1.9**	222	**1.9**	39	**0.3**
		2013	13,561	**95.6**	258	**1.8**	337	**2.4**	33	**0.2**
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**2012**	**9,629**	**98.1**	**52**	**0.5**	**104**	**1.1**	**29**	**0.3**
		2013	**11,384**	**98.2**	**64**	**0.6**	**112**	**1.0**	**32**	**0.3**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2012	2,287	**98.2**	18	**0.8**	17	**0.7**	7	**0.3**
		2013	2,679	**98.1**	23	**0.9**	23	**0.8**	6	**0.2**
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2012	7,342	**98.1**	34	**0.4**	87	**1.2**	22	**0.3**
		2013	8,705	**98.2**	41	**0.5**	89	**1.0**	25	**0.3**
3	**विदेशी बैंक**	**2012**	**2,284**	**97.3**	**21**	**0.9**	**22**	**0.9**	**20**	**0.8**
		2013	**2,610**	**97.0**	**29**	**1.1**	**27**	**1.0**	**23**	**0.9**
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**2012**	**50,168**	**97.2**	**695**	**1.3**	**617**	**1.2**	**109**	**0.2**
		2013	**57,951**	**96.8**	**909**	**1.5**	**900**	**1.5**	**123**	**0.2**

टिप्पणी: 1. पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।
2. *: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. **: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां।

चार्ट IV.11: बैंक समूहवार गिरावट अनुपात

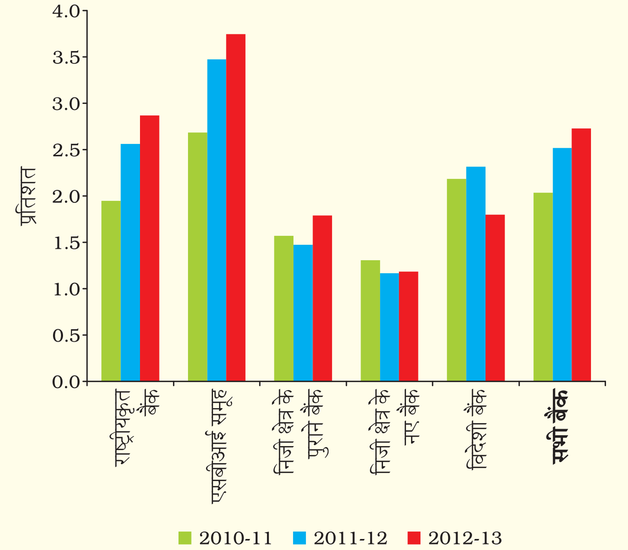

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

चार्ट IV.12: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित अग्रिम

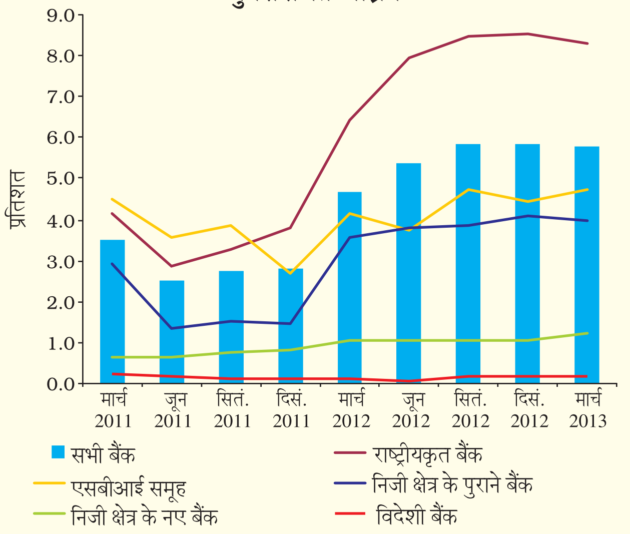

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां।

4.21 स्लिपेज अनुपात, जिसे वर्ष के आरंभ में मानक अग्रिमों के प्रतिशत के तौर पर अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है, में भी 2012-13 के दौरान वृद्धि देखने में आई (सारणी IV .11)।

4.22 समग्र स्तर पर, मार्च 2013 के अंत में सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों का अनुपात 5.8 प्रतिशत रहा। यह राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सबसे उच्च (8.3 प्रतिशत) था और इसके बाद स्टेट बैंक समूह (4.7 प्रतिशत) का था (सारणी IV.12)।

कंपनी ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रणाली के तहत पुनर्संरचित ऋणों में तीव्र वृद्धि

4.23 2012-13 में सीडीआर प्रणाली के तहत पुनर्संरचित ऋणों में तीव्र वृद्धि देखी गई। सीडीआर प्रणाली में केवल ऐसे बहु बैंकिंग खातों और सिंडिकेशन/संघीय खातों को शामिल किया जाता है, जहां सभी बैंकिंग संस्थाओं की समग्र बकाया वसूली की रकम 100 मिलियन या इससे अधिक होती है। 2012-13 में इस प्रणाली के तहत पुनर्संरचना के लिए अनुमोदित मामलों की कुल संख्या में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस तरह पुनर्संरचित ऋण में 52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई जो 2011-12 में हुई वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि को दर्शाती है (सारणी IV.15)। 2013-14 की पहली तिमाही में ऐसे मामलों की संख्या और ऋण की राशि में मामूली कमी आई है।

4.24 लोहा तथा इस्पात, और बुनियादी आधारभूत संरचना सबसे अधिक दबाव झेलने वाले क्षेत्र थे। मार्च 2013 के अंत में, कुल पुनर्संरचित ऋणों में लोहा और इस्पात का हिस्सा 23 प्रतिशत था, जबकि कुल पुनर्संरचित ऋण में आधारभूत संरचना (विद्युत और दूरसंचार सहित) का हिस्सा 22.7 प्रतिशत के साथ लगभग समान था[9]।

सारणी IV.15: सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्गठित ऋण की प्रवृत्ति

समाप्त अवधि	अनुमोदित मामलों की संख्या	समग्र ऋण (बिलियन रुपये में)
मार्च 2012	292 (20.7)	1,505 (35.7)
मार्च 2013	401 (37.3)	2,290 (52.2)
जून 2013	415 (34.3)	2,503 (48.6)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की समवर्ती अवधि की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।
स्रोत: सीडीआर कक्ष।

[9] सीडीआर प्रकोष्ठ आधारभूत संरचना, विद्युत और दूरसंचार के वर्गों के अंतर्गत पुनर्संरचित ऋण के लिए अलग-अलग डेटा उपलब्ध कराता है। यहाँ उल्लिखित हिस्से से तात्पर्य इन तीन वर्गों के कुल हिस्से को एक साथ मिलाया गया है।

गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र - एनपीए में वृद्धि का प्रमुख कारक

4.25 हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एनपीए अनुपात गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के एनपीए अनुपात से लगातार अधिक रहा है, लेकिन 2012-13 में आस्ति- गुणवत्ता में ह्रास मुख्यतः गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कारण रहा (सारणी IV.16; चार्ट IV.13)।

4.26 घरेलू बैंकों के कुल ऋणों में आधे से कुछ कम हिस्सा रखने वाले उद्योगों की आस्ति- गुणवत्ता में भी हाल के वर्षों में लगातार गिरावट दिखी है, खास तौर से 2012-13 [10] में। कुल औद्योगिक ऋणों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखने वाले आधारभूत संरचना क्षेत्र के एनपीए अनुपात में इस अवधि में तेजी का रुख देखा गया (चार्ट- IV.14)। इसके विपरीत, खुदरा क्षेत्र में एनपीए अनुपात में गिरावट का रुख रहा।

सरफेसी अधिनियम एनपीए वसूली का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बना रहा

4.27 वर्ष 2012-13 में, एनपीए वसूली के तीन माध्यमों अर्थात वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट), ऋण वसूली न्यायाधिकरण(डीआरटी) और लोक अदालत- में से सबसे ज्यादा

सारणी 16: देशी बैंकों का क्षेत्र-वार एनपीए*

(राशि बिलियन रुपये में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से: कृषि		माइक्रो तथा लघु उद्यम		अन्य		गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कुल एनपीए	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
सरकारी क्षेत्र के बैंक												
2012	**562**	**50.0**	**227**	**20.2**	**174**	**15.5**	**161**	**14.3**	**563**	**50.0**	**1,125**	**100.0**
2013	**669**	**42.9**	**280**	**18.0**	**284**	**18.2**	**105**	**6.7**	**890**	**57.1**	**1,559**	**100.0**
राष्ट्रीयकृत बैंक**												
2012	323	48.4	129	19.3	134	20.0	60	9.1	345	51.6	668	100.0
2013	405	42.2	156	16.3	178	18.6	70	7.3	554	57.8	959	100.0
एसबीआई समूह												
2012	239	52.3	98	21.4	41	9.0	100	22.0	218	47.7	457	100.0
2013	264	44.1	124	20.7	106	17.6	35	5.8	335	55.9	599	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक												
2012	**51**	**27.9**	**22**	**11.8**	**17**	**9.4**	**12**	**6.7**	**132**	**72.1**	**183**	**100.0**
2013	**52**	**26.0**	**22**	**10.9**	**20**	**9.9**	**11**	**5.3**	**148**	**74.0**	**200**	**100.0**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक												
2012	18	42.9	6	13.4	7	16.8	5	12.8	24	57.1	42	100.0
2013	19	36.8	6	12.2	7	13.9	6	10.7	33	63.2	52	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक												
2012	33	23.4	16	11.3	10	7.2	7	4.9	108	76.6	141	100.0
2013	33	22.2	15	10.4	12	8.5	5	3.3	115	77.8	148	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक												
2012	**613**	**46.9**	**249**	**19.0**	**191**	**14.7**	**173**	**13.2**	**695**	**53.1**	**1,308**	**100.0**
2013	**721**	**41.0**	**302**	**17.2**	**304**	**17.3**	**116**	**6.5**	**1,038**	**59.0**	**1,759**	**100.0**

टिप्पणी: 1. * : विदेशी बैंक शामिल नहीं।
2. रा.-राशि, प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।
3. **- आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
4. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि उपर्युक्त मदें कुल से मेल न खाएं।

स्रोत : बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

[10] उद्योग और आधारभूत संरचना के समग्र एनपीए और अग्रिमों के आंकड़े सितंबर 2012 के पहले और बाद में सख्ती से तुलनीय नहीं हैं क्योंकि आस्ति गुणवत्ता में उद्योग-वार एक्सपोजर को पकड़ने के लिए सितंबर 2012 में विवरणी के लिए एक नया फार्मेट शुरू किया गया है। तथापि, इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के पश्चात, उद्योग और आधारभूत संरचना के एनपीए अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति सितंबर 2012 के पहले और बाद में अभी भी काफी अधिक है।

चार्ट IV.13:प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की एनपीए की प्रवृत्ति

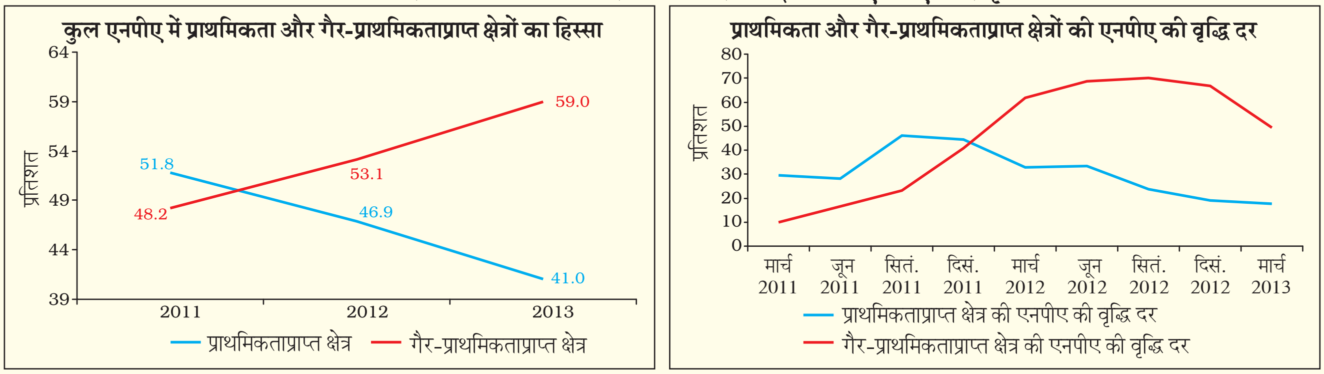

स्रोत: देशी बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियां ।

चार्ट IV.14: चुनिंदा क्षेत्रों का सकल एनपीए अनुपात

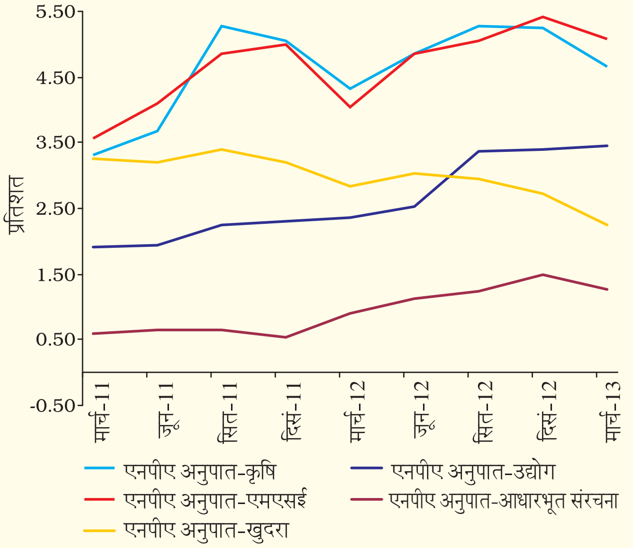

टिप्पणी: देशी बैंकों की ऑफ-साइट विवरणियां ।

राशि सरफेसी अधिनियम द्वारा वसूली गई। इस अधिनियम द्वारा वसूली गई एनपीए की राशि कुल एनपीए की राशि का लगभग 80 प्रतिशत थी। यद्यपि संदर्भित मामलों की कुल संख्या की दृष्टि से 80 प्रतिशत भाग के साथ लोक अदालतें सबसे प्रमुख रहीं; इसका कारण यह है कि इन अदालतों ने कम राशि वाले ऐसे अधिक मामले निपटाए, जहां प्रत्येक मामले की अधिकतम सीमा 20,00,000 रुपये थी (सारणी- IV.17)।

बैंक प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों की प्रतिभूतिकृत आस्तियों में सबसे बड़े अभिदाता बने रहे, किंतु उनका हिस्सा घटता गया

4.28 प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा प्रतिभूतिकृत की गई कुल आस्तियों में सबसे बड़ा योगदान बैंकों का था।

सारणी IV.17: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए (राशि बिलियन रुपये में)

वसूली चैनल	2011-12				2012-13			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की गई राशि *	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	4,76,073	17	2	11.8	8,40,691	66	4	6.1
ii) डीआरटी	13,365	241	41	17.0	13,408	310	44	14.0
iii) सरफेसी अधिनियम	1,40,991	353	101	28.6	1,90,537	681	185	27.1
कुल	**6,30,429**	**611**	**144**	**23.6**	**10,44,636**	**1,058**	**232**	**21.9**

टिप्पणी: 1. *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि , जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।
2. डीआरटी- ऋण वसूली न्यायाधिकरण।

सारणी IV.18: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि बिलियन रुपये में)

	मद	जून 2012 के अंत में	जून 2013 के अंत में
	1	2	3
1	अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	805	885
2	एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें	167	189
3	निम्नलिखित के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीद		
	(क) बैंक	116	126
	(ख) एससी /आरसी	36	45
	(ग) एफआईआई	1	1
	(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	15	17
4	पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	82	101

स्रोत : प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

तथापि, पिछले कुछ वर्षों से उनका हिस्सा लगातार घट रहा है (सारणी IV.18; चार्ट IV.15)।

प्रावधानीकरण

समग्र स्तर पर प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में हल्की गिरावट

4.29 यद्यपि 2012-13 में सकल एनपीए अनुपात में वृद्धि हुई, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात, जिसे सकल एनपीए के प्रतिशत के रूप में ऋण हानि के लिए प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया

चार्ट IV.15: एससी/आरसी की कुल प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों में संस्थाओं का हिस्सा

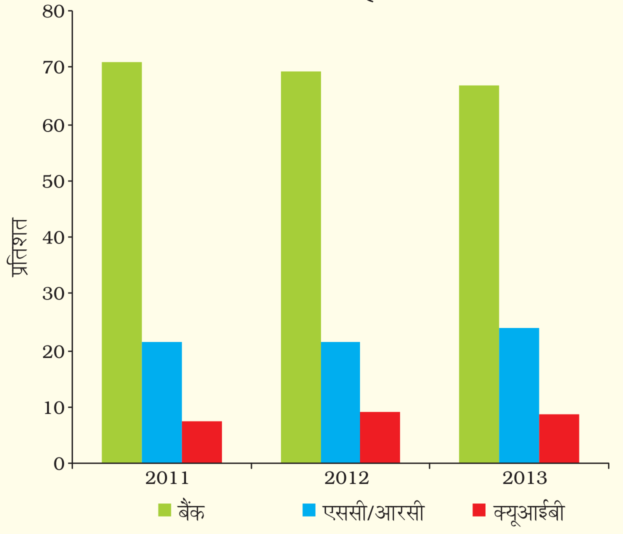

टिप्पणी: क्यूआईबी - अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता।

चार्ट IV.16: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

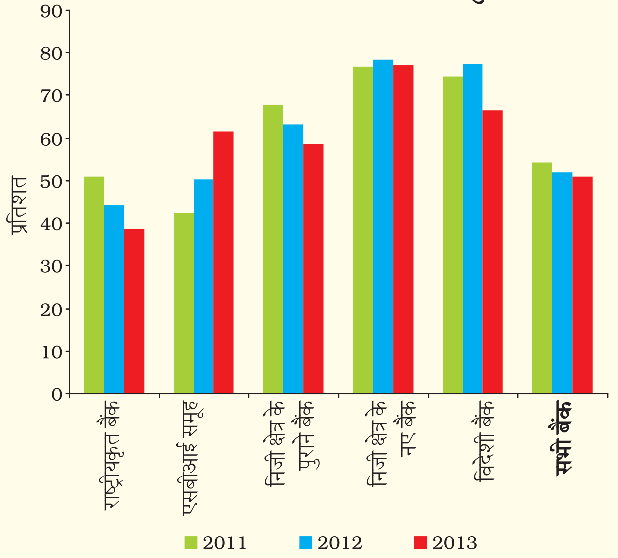

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियां ।

है, में वर्ष के दौरान समग्र स्तर पर हल्की गिरावट आई। राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह गिरावट सबसे ज्यादा परिलक्षित हुई (चार्ट IV.16)। लेकिन, स्टेट बैंक समूह के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में 2011 से निरंतर सुधार हुआ है। इस अवधि में बढ़ते एनपीए अनुपात की पृष्ठभूमि में इस स्थिति को इस बैंक समूह के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में माना जा सकता है ।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार वितरण

सभी उत्पादक क्षेत्रों की ऋण संवृद्धि में मंदी

4.30 वर्ष 2012-13 में सभी उत्पादक क्षेत्रों अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण की संवृद्धि में मंदी दर्ज की गई (सारणी IV.19)। सबसे तेज मंदी कृषि और सहायक गतिविधियों में आई। उद्योगों के अंतर्गत आधारभूत संरचना क्षेत्र की ऋण वृद्धि में मंदी आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिए गए ऋण, जो सेवा क्षेत्र के कुल ऋण के लगभग पांचवां भाग हैं, में कमी सेवा क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में समग्र मंदी के एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं (चार्ट IV. 17)। इन सबके विपरीत, खुदरा ऋण ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा, जिसने 2012-13 में अपनी संवृद्धि बनाए रखी।

सारणी IV.19 : सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार नियोजन

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र	को बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
		मार्च 2012	मार्च 2013	2011-12	2012-13
1	**कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां**	**5,484**	**5,899**	**14.1**	**7.6**
2	**उद्योग,** *जिसमें से*	**19,374**	**22,302**	**20.7**	**15.1**
	2.1 मूलभूत सुविधाएं	6,300	7,297	20.8	15.8
	2.2 माइक्रो तथा लघु उद्योग	2,363	2,843	12.4	20.3
3	**सेवाएं,** *जिसमें से*	**10,166**	**11,486**	**14.5**	**13.0**
	3.1 व्यापार	2,245	2,760	21.3	22.9
	3.2 वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र	1,126	1,261	15.7	12.0
	3.3 पर्यटन, होटल तथा रेस्तराँ	323	354	16.7	9.9
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	143	169	3.0	18.4
	3.5 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	2,278	2,570	24.0	12.8
4	**व्यक्तिगत ऋण** *जिसमें से*	**7,873**	**9,009**	**13.4**	**14.4**
	4.1 क्रेडिट कार्ड बकाया	204	249	12.9	21.9
	4.2 शिक्षा	498	550	16.6	10.4
	4.3 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	4,013	4,600	12.6	14.6
	4.4 सावधि जमाराशियोंकी जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर(बी), एनआरएनआर जमाराशियां आदि, सहित)	569	611	15.4	7.3
5	**खाद्येतर ऋण (1 से 4)**	**42,897**	**48,696**	**17.0**	**13.5**
6	**सकल बैंक ऋण**	**43,714**	**49,642**	**17.1**	**13.6**

टिप्पणी: आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत : बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक नियोजन ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

2012-13 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में तेजी

4.31 वर्ष के दौरान कुल ऋण संवृद्धि में आई गिरावट की तुलना में 2012-13 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि में तेजी देखने

चार्ट IV.17: प्रमुख क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि

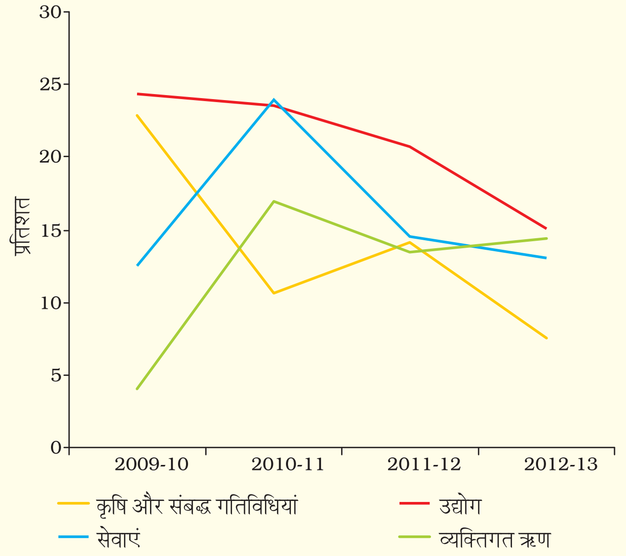

स्रोत: बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक नियोजन।

में आई। लेकिन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की ऋण संवृद्धि, कुल ऋण संवृद्धि से कम रही (चार्ट IV.18)।[11]

समग्र स्तर पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण का हिस्सा लक्ष्य से कम था

4.32 वर्ष 2012-13 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिया गया ऋण क्रमशः 36.3 प्रतिशत और 37.5 प्रतिशत रहा (समायोजित निवल बैंक ऋण/ तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि का, जो भी अधिक हो) जो 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य की तुलना में कमी को दर्शाता है (सारणी IV.20)।

बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के वितरण में अग्रणी भूमिका निभाई

4.33 मार्च 2013 के अंत तक जारी कुल किसान क्रेडिट कार्ड में 63 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक बैंक इनके वितरण में अग्रणी थे। कुल जारी कार्डों में सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 21 प्रतिशत था और बाकी 16 प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों

[11] ये आंकड़े बैंकों के घरेलू परिचालन के आधार पर उनकी ऑफ-साइट विवरणियों से लिए गए हैं। इसलिए यहाँ सूचित की गई समग्र ऋण वृद्धि, हो सकता है कि बैंकों के तुलन पत्र से लिए गए आंकड़ों के आधार पर, पूर्व में सूचित समग्र ऋण वृद्धि से मेल न खाए।

चार्ट IV.18: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में वृद्धि

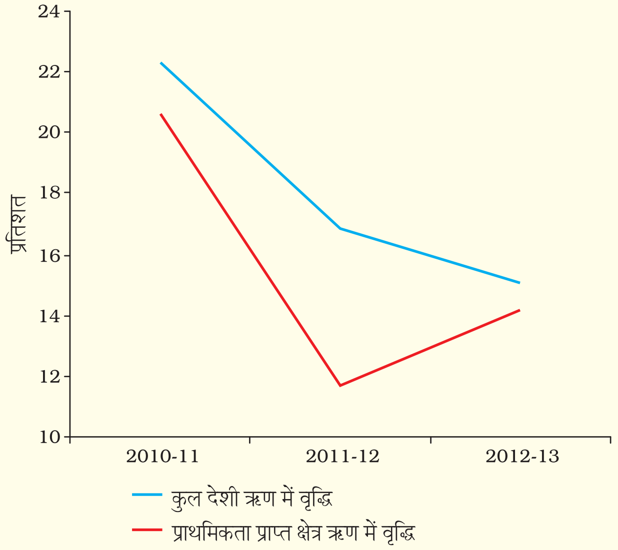

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

चार्ट IV.19: जारी किए गए कुल केसीसी में संस्थाओं का हिस्सा

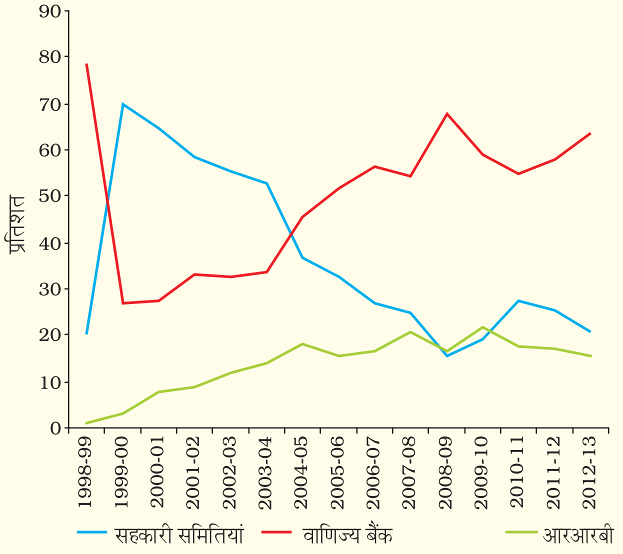

स्रोत: नाबार्ड और वाणिज्य बैंकों से विवरणी।

का था (चार्ट IV.19; परिशिष्ट सारणी IV.3)। वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी घटी है।

खुदरा ऋण

समग्र ऋण संवृद्धि में मंदी की अवधि में भी खुदरा ऋण में तेजी बनी रही

4.34 2012-13 में खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष की तरह द्विअंकीय वृद्धि दिखी (सारणी IV.21)। यह उल्लेखनीय है कि ऋण संवृद्धि में व्यापक मंदी की अवधि में भी, खुदरा ऋणों की संवृद्धि कायम रही।

4.35 2012-13 में भी खुदरा ऋणों में संवृद्धि इसलिए बनी रही क्योंकि आवास कर्ज, जो खुदरा ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा है, में निरंतर द्विअंकीय बढ़त जारी रही और वाहन कर्ज की संवृद्धि में तेजी आई, जो खुदरा ऋण का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों की संवृद्धि में बढ़त ने भी खुदरा ऋण की समग्र वृद्धि में योगदान किया, हालांकि कुल खुदरा ऋण में इसका हिस्सा 4 प्रतिशत से भी कम रहा।

सारणी IV.20: बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

(31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक	
	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक क्षेत्र के कुल अग्रिम	**12,836**	**36.3**	**3,274**	**37.5**	**1,033**	**35.2**
जिसमें से						
कृषि	5,306	15.0	1,119	12.8	72	2.4
दुर्बल वर्ग	3,473	9.8	505	5.7	55	1.9
माइक्रो और लघु उद्यम	4,784	13.5	1,417	16.2	283	9.6

टिप्पणी: 1. आंकडे अनंतिम हैं।

2. 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य को मार्च 2018 तक प्राप्त किया जाना है। 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की राशि के समतुल्य ऋण (ओबीसी), पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 32 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

सारणी IV.21: बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	बकाया राशि		प्रतिशत घट-बढ़	
		2012	2013	2011-12	2012-13
1		2	3	4	5
1	आवास ऋण	4,118	4,754	14.2	15.4
2	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	27	34	-41.0	25.3
3	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	223	268	19.6	20.1
4	ऑटो ऋण	1,162	1,421	16.0	22.3
5	अन्य व्यक्तिगत ऋण	3,069	3,618	24.3	17.9
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)		**8,599** (18.4)	**10,095** (18.8)	**17.6**	**17.4**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के हिस्से को प्रतिशत में दर्शाते हैं। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफसाइट विवरणियों (देशी) में दिए अनुसार हैं।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत : ऑफसाइट विवरणी पर आधारित (देशी)।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

समग्र ऋण संवृद्धि में मंदी की अवधि में भी संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋण में तेजी आई

4.36 विगत में, संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात, स्थावर संपदा, पूंजी बाजार और पण्यों को दिए गए ऋण में वृद्धि ने आम तौर पर समग्र ऋण में संवृद्धि जैसे पैटर्न का अनुगमन किया (परिशिष्ट सारणी IV.4)। लेकिन, 2012-13 में संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग दो गुनी वृद्धि मुख्यतयः स्थावर संपदा क्षेत्र को दिए गए ऋण के कारण रही। इस विस्तार को 2012-13 में सभी टियर I और टियर II के कई शहरों में आवास की कीमतों में भारी तेजी से जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता है।[12]

6.पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

2012-13 में बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम से जुटाए गए संसाधनों में कमी आई

4.37 द्वितीयक बाजार के धीमे प्रदर्शन और ऋणों के कम उठाव को देखते हुए, बैंक 2012-13 में सार्वजनिक निर्गम से करीब 3 बिलियन रुपए ही जुटा पाए (सारणी IV.22)।

4.38 बैंक सार्वजनिक निर्गम की तुलना में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ज्यादा राशि जुटाते हैं; 2012-13 भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं रहा (सारणी IV.23)। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बरकरार रहने के कारण, बैंकों ने 2012-13 में अमरीकन / वैश्विक निक्षेपागार रसीदों के निर्गम से धन नहीं जुटाया।

2012-13 के ज्यादातर हिस्से में बीएसई बैंकेक्स ने बीएसई सेंसेक्स को पछाड़ा

4.39 विगत की तरह, 2012-13 में बीएसई बैंकेक्स, बीएसई सेंसेक्स से बेहतर रहा, जो बैंक स्टॉक के सापेक्षिक रूप से अच्छे प्रदर्शन को दर्शाता है। पहली तिमाही को छोड़कर बाकी पूरे साल बैंकेक्स में लगातार तेजी आई, जिसका कारण अंशतः विदेशी संस्थागत निवेश के अधिक अंतर्वाह के साथ-साथ प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई गैर पारंपरिक मौद्रिक नीतियां रहीं (चार्ट IV.20)। यद्यपि, साल की आखिरी तिमाही में बैंकेक्स में गिरावट का रुख रहा जिसके परिणामस्वरूप यह बीएसई सेंसेक्स के धरातल पर आ गया, इसका कारण वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता और घरेलू अर्थव्यवस्था में आई मंदी थी।

सारणी IV.22 : बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि बिलियन रुपये में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		**कुल योग**
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	**8=(6+7)**
2011-12	-	-	-	-	-	-	-
2012-13	-	-	3	-	3	-	**3**

टिप्पणी: - शून्य / नगण्य।
स्रोत: सेबी।

[12] देखें एनएचबी रेसीडेक्स 2012-13 के तिमाही आंकड़े <nhb.org.in> पर

सारणी IV.23: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि बिलियन रुपये में)

श्रेणी	2011-12		2012-13	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	11	62	21	171
सरकारी क्षेत्र के बैंक	9	44	12	91
कुल	**20**	**106**	**33**	**262**

टिप्पणी:- 2012-13 के लिए डेटा अनंतिम है।
स्रोत: - मर्चेन्ट बैंकर्स और वित्तीय संस्थाएं।

चार्ट IV.20: 2012-13 के बैंकेक्स और सेंसेक्स का तुलनात्मक निष्पादन

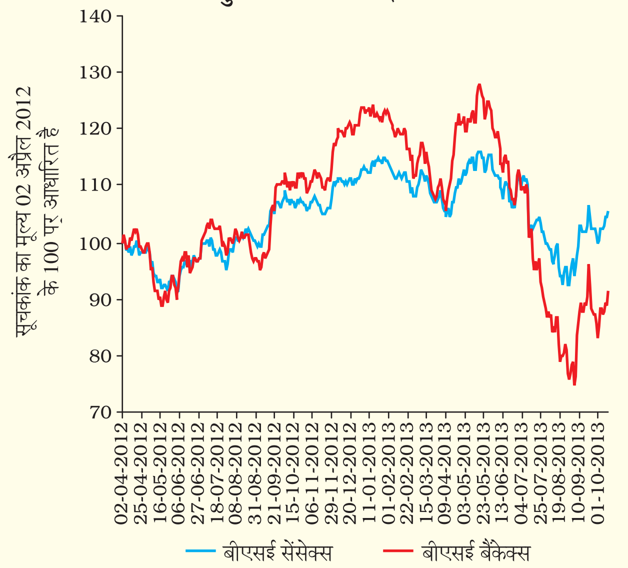

4.40 वर्ष 2012-13 में बैंक स्टॉक में तेजी की वजह मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक की बजाय निजी क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक में तेजी रही (परिशिष्ट सारणी 5; चार्ट IV.21)।

4.41 बैंकेक्स पर प्रतिलाभ के मामले में, 2012-13 में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में इसमें घट-बढ़ भी अधिक थी। यह अधिक प्रतिफल को दर्शाता है लेकिन साथ ही बैंक स्टॉक की ट्रेडिंग में अधिक जोखिम को भी दर्शाता है (सारणी IV.24)।

7.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के स्वामित्व का स्वरूप

बैंकिंग क्षेत्र का स्वरूप मुख्यत: सार्वजनिक है

4.42 मार्च 2013 के अंत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में से 73 प्रतिशत आस्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की थीं। वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भागीदारी का रुख बढ़त का रहा है (चार्ट IV.22)।

बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर निम्न बना हुआ है

4.43 सार्वजनिक स्वामित्व की प्रमुखता के बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर काफी कम है,

चार्ट IV.21: बैंकों के स्टॉक मूल्यों में प्रतिशत घट-बढ़

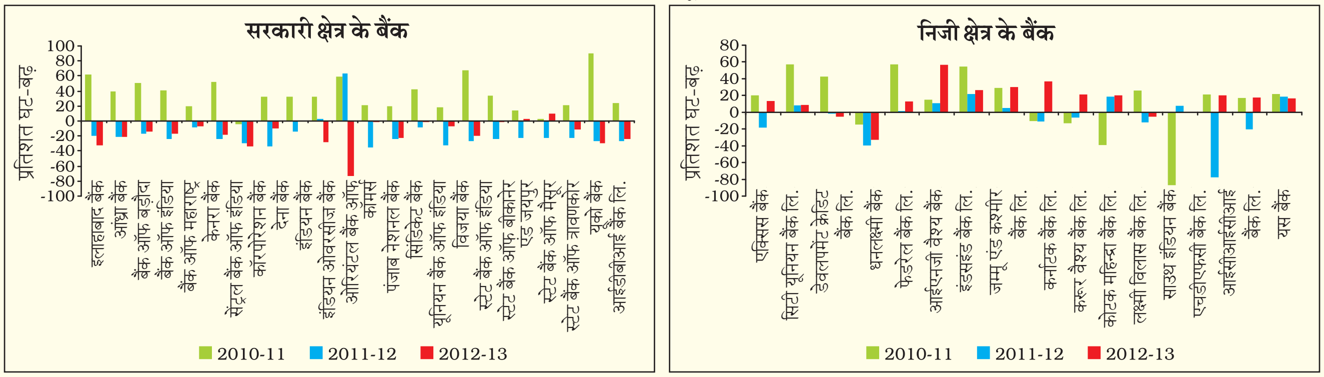

टिप्पणी: 2011-12 और 2012-13 के बीच साउथ इंडियन बैंक और देना बैंक के अंतिम स्टॉक मूल्य में कोई घट-बढ़ नहीं पाया गया।
स्रोत: बीएसई।

सारणी IV.24 जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	24.9	-11.6	10.9	-15.9
बीएसई सेंसेक्स	10.9	-10.5	8.2	2.9
2. घट-बढ़@				
बीएसई बैंकेक्स	10.3	9.7	9.3	11.0
बीएसई सेंसेक्स	6.3	6.2	6.4	3.3
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा	**9.5**	**11.4**	**13.3**	**13.0$**
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा**	**11.9**	**11.5**	**12.2**	**12.2$**

टिप्पणी: 1. * : अंक- दर- अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घट-बढ़।
2. @ : घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।
3. **: अवधि के अंत में।
4. #: अप्रैल - सितम्बर 2013; $: अप्रैल - जून 2013।
स्रोत : ब्लूमबर्ग और बीएसई।

चार्ट IV.22: बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों का हिस्सा

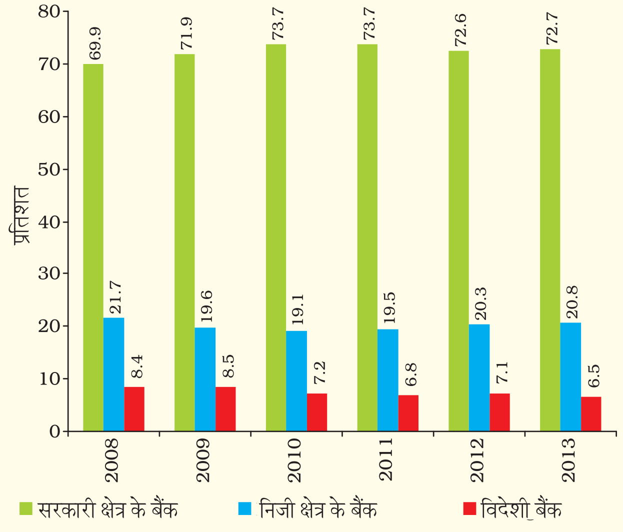

स्रोत: बैंकों के वार्षिक लेखे।

जो सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली की प्रमुखता वाले कतिपय अन्य देशों जैसे-चीन की स्थिति से अलग है। साथ ही, हाल के वर्षों में संकेंद्रण की मात्रा में लगातार गिरावट आई है (बॉक्स IV. 3)।

बॉक्स IV.3:
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति संकेंद्रण

किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, अन्य कारकों जैसे प्रवेश/निकास बैरियर और मूल्य/उत्पाद विभेदन के साथ उस क्षेत्र में संकेंद्रण के स्तर पर भी निर्भर करती है। संबंधित साहित्य और अनुभवजन्य साक्ष्य बैंकिंग उद्योग में संकेंद्रण के लाभ और हानि दोनों को दर्शाते हैं।[13]लाभ के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि (क) अधिक संकेंद्रित बैंकिंग क्षेत्र पर प्रणालीगत संकट का प्रभाव कम पड़ता है; (ख) अनेक छोटे खिलाड़ियों का पर्यवेक्षण करने की बजाय कुछ बड़े खिलाड़ियों पर नजर रखना प्रायः ज्यादा आसान होता है। वहीं दूसरी ओर, (क) अधिक संकेंद्रण से अक्सर ब्याज दरें ऊंची हो जाती हैं, क्योंकि देनदार आपस में सांठ-गांठ कर सकते हैं; (ख) अधिक संकेंद्रित बैंकिंग क्षेत्र में टू-बिग-टू-फेल के जोखिम ज्यादा गंभीर होते हैं; (ग) यह देखा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र जितना ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होता है, इस बात की संभावना कम है कि देश को प्रणालीगत बैंकिंग संकट से सामना करना पड़े *(वही)*।

संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी उच्च संकेंद्रण देखा गया है (सारणी 1)। एक रोचक तथ्य यह है कि चीनी बैंकिंग क्षेत्र का संकेंद्रण तुलनात्मक रूप से काफी ऊंचा है जो मुख्यतः सार्वजनिक स्वरूप का है। इसके विपरीत, सार्वजनिक स्वामित्व का प्रभुत्व होने के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण काफी कम स्तर पर रहा है।

सारणी 1: बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण की मात्रा

देश	संकेंद्रण माप	देश	संकेंद्रण माप
जर्मनी	78.1	चीन	51.5
दक्षिण अफ्रीका	77.8	जापान	44.6
ऑस्ट्रेलिया	69.0	अर्जेंटीना	35.6
फ्रांस	62.7	यूएसए	35.4
ब्राजील	62.6	रूस	31.7
यूके	57.8	*भारत*	*29.4*

टिप्पणी: संकेंद्रण माप का तात्पर्य, कुल बैंकिंग आस्तियों में शीर्ष के तीन बैंकों के हिस्से से है। माप के अनुसार देशों की रैंकिंग अवरोही क्रम में की गई है। डेटा 2011 के हैं।
स्रोत: फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेटाबेस, वर्ल्ड बैंक।

आर्थिक सुधारों के आरंभ से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए विलयों और अधिग्रहणों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2000 के दशक में समेकन ने जोर पकड़ा। 1989-90 से अब तक हुए 28 विलयों में से 16 विलय 2014 के दशक में हुए।[14]

(जारी...)

[13] देखें बेक एट आल (2003)।

[14] यह जानकारी मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2006-08 तथा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न अंकों से ली गई है।

(...समाप्त)

हालांकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संकेंद्रण की सीमा, जो कम ही रही है, इस दशक के दौरान घटी है (सारणी 2)। इसका अर्थ यह है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उच्च समेकन अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों के संकेंद्रण में तेजी नहीं आई।

सारणी 2: भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से संबंधित संकेंद्रण माप

माप	2000	2006	2013
सीआर$_3$	33.9	32.0	27.7
सीआर$_5$	43.7	40.8	37.4
एलआर	0.724	0.683	0.603
एचआई (सामान्यीकृत)	0.065	0.045	0.040

टिप्पणी: सीआर$_3$/सीआर$_5$ बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में सबसे शीर्ष के 3/5 वाणिज्य बैंकों के हिस्से को दर्शाता है। एलआर, लोरेंज़ कर्व संबंधी संकेंद्रण सहगुणांक को दर्शाता है और यह इस फार्मुला के आधार पर निकाला जाता है: $1 - \sum (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$, जहां K की शुरुआत 0 से होती है और यह n-1 पर समाप्त होती है; X, संस्थाओं का संचयी अनुपात है; Y, आस्तियों में संचयी अनुपात का हिस्सा है। सहगुणांक का दायरा 0 और 1 के बीच का है, जिसमें 0 बिलकुल बराबर हिस्से को दर्शाता है और 1 स्पष्ट एकाधिकार को दर्शाता है।

H1, सामान्यीकृत हरफिन्दह्ल सूचकांक है जिसकी परिभाषा (H-1/N)/(1-1/N) है, जहां N, बैंकों की कुल संख्या है और H, सामान्य हरफिन्दह्ल सूचकांक है जिसकी परिभाषा $H = \sum_{i=1}^{N} S_i^2$ है, जहां S_i,बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में 'i'th बैंक का हिस्सा है। H1 का दायरा 0 से 1 है।

स्रोत: भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी के आधार पर परिकलित।

संदर्भ:

बेक, टी. असली डीमिरजक-कुंट एंड रोस लेविन (2003), "बैंक कंसेंट्रेशन एंड क्राइसिस", एनबीईआर वर्किंग पेपर नं. 9921।

बिक्कर, जे.ए. एंड के. हाफ (2000), "मीजर्स ऑफ काम्पिटिशन एंड कंसेंट्रेशन इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री: ए रिव्यू ऑफ लिट्रेचर", दि नीदरलैंडश बैंक, रिसर्च सीरीज सुपरविज़न नं. 7।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सार्वजनिक शेयरधारिता की वृद्धि की ओर रुझान

4.44 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हाल के वर्षों में उच्चतर सार्वजनिक शेयरधारिता के प्रति क्रमिक झुकाव आया है। 2011 से 2013 के बीच 51 प्रतिशत के सांविधिक स्तर के आस- पास शेयर रखने वाले बैंकों के प्रतिशत में गिरावट आई। इसके विपरीत, सांविधिक स्तर से काफी अधिक (81 प्रतिशत से अधिक) सार्वजनिक शेयरधारिता वाले बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी IV.25 परिशिष्ट सारणी IV.6 के साथ पठित)। जैसी कि पहले चर्चा की गई है, हाल के वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को काफी अधिक पूंजी समर्थन दिया है (सारणी IV.12 देखें)।

सारणी IV.25: पब्लिक शेयरधारिता के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या

शेयरधारिता की श्रेणी	2011	2012	2013
1	2	3	4
51 प्रतिशत से अधिक और 61 प्रतिशत तक	10 (47.6)	9 (42.9)	9 (42.9)
61 प्रतिशत से अधिक और 71 प्रतिशत तक	6 (28.6)	7 (33.3)	5 (23.8)
71 प्रतिशत से अधिक और 81 प्रतिशत तक	3 (14.3)	4 (19.0)	4 (19.0)
81 प्रतिशत से अधिक	2 (9.5)	1 (4.8)	3 (14.3)
कुल	**21** **(100.0)**	**21** **(100.0)**	**21** **(100.0)**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों ,भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

8. विदेशी बैंकों का भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

विदेश में भारतीय बैंकों की संवृद्धि, भारत में विदेशी बैंकों की संवृद्धि से अधिक रही

4.45 यद्यपि भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों की शाखाओं की संख्या, विदेश में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों की शाखाओं से अधिक है, फिर भी हाल के वर्षों में भारतीय बैंकों की संवृद्धि विदेशी बैंकों की तुलना में अधिक रही है। मार्च 2013 के अंत तक 43 विदेशी बैंकों की 331 शाखाएं भारत में कार्य कर रही थीं; जबकि विदेश में 24 भारतीय बैंकों की 171 शाखाएं थीं (सारणी IV.26;चार्ट IV.23)।

4.46 हालांकि भारतीय बैंक विदेशों में अनुषंगी संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, मार्च 2013 के अंत तक विदेशी बैंक भारत में केवल

सारणी IV.26: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन
(मार्च के अंत में)

बैंक का नाम			शाखा		सहायक संस्था		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		अन्य कार्यालय*		कुल	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	**2012**	**2013**
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	**12**	**13**
I.	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**		**150**	**155**	**21**	**20**	**38**	**36**	**6**	**7**	**22**	**29**	**237**	**247**
	1	इलाहाबाद बैंक	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**	**2**
	2	आंध्रा बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
	3	बैंक ऑफ बड़ौदा	47	51	9	9	2	1	1	2	8	9	**67**	**72**
	4	बैंक ऑफ इंडिया	24	25	4	4	5	4	0	0	0	0	**33**	**33**
	5	केनरा बैंक	5	5	0	0	1	1	0	0	0	0	**6**	**6**
	6	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**0**	**1**
	7	कॉर्पोरेशन बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
	8	इंडियन बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**4**
	9	इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	0	0	3	3	0	0	3	3	**12**	**12**
	10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
	11	पंजाब नेशनल बैंक	4	4	3	3	5	5	1	1	0	0	**13**	**13**
	12	भारतीय स्टेट बैंक	52	51	5	4	8	7	4	4	11	17	**80**	**83**
	13	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
	14	सिंडिकेट बैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
	15	यूको बैंक	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0	**5**	**4**
	16	यूनियन बैंक	1	2	0	0	5	5	0	0	0	0	**6**	**7**
	17	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	**1**	**2**
	18	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
II.	**निजी क्षेत्र के बैंक**		**15**	**16**	**3**	**3**	**17**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**37**
	19	ऐक्सिस बैंक	4	4	0	0	3	3	0	0	0	0	**7**	**7**
	20	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2	2	0	0	2	3	0	0	0	0	**4**	**5**
	21	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9	10	3	3	8	8	0	0	0	0	**20**	**21**
	22	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	**2**	**2**
	23	फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
	24	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**1**	**1**
सभी बैंक			**165**	**171**	**24**	**23**	**55**	**54**	**6**	**7**	**22**	**29**	**272**	**284**

* अन्य कार्यालयों में विपणन/उप-कार्यालय, विप्रेषण केंद्र इत्यादि शामिल हैं।
स्रोत: रिज़र्व बैंक।

शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे थे, उनकी कोई अनुषंगी संस्थाएं नहीं थीं। शाखाओं और अनुषंगी संस्थाओं की संख्या मिलाकर देखें तो भारतीय बैंकों की विदेशी बाजारों में उपस्थिति, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है (चार्ट-

चार्ट IV.23: विदेश स्थित भारतीय बैंकिंग केंद्रों और भारत स्थित विदेशी बैंकिंग केंद्रों के बीच तुलना

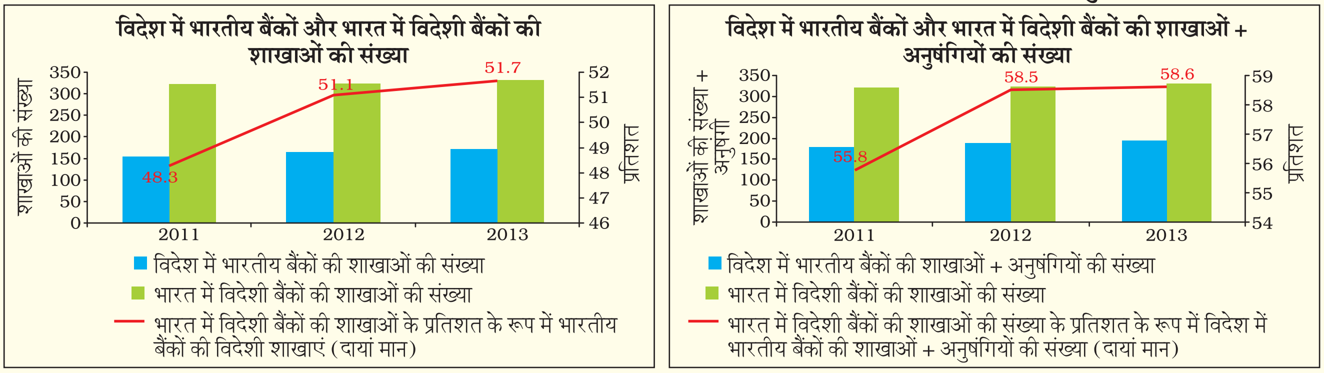

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.24: विदेशी बैंकिंग केंद्रों की संरचना (शाखाएं + अनुषंगी)

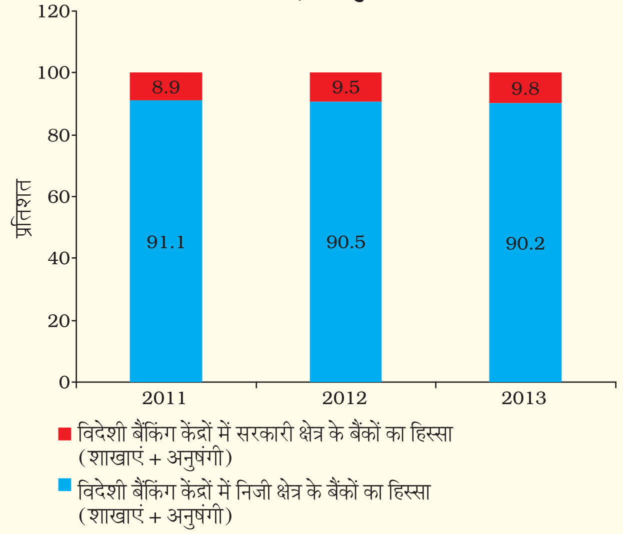

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.25: एटीएम की वृद्धि और संरचना

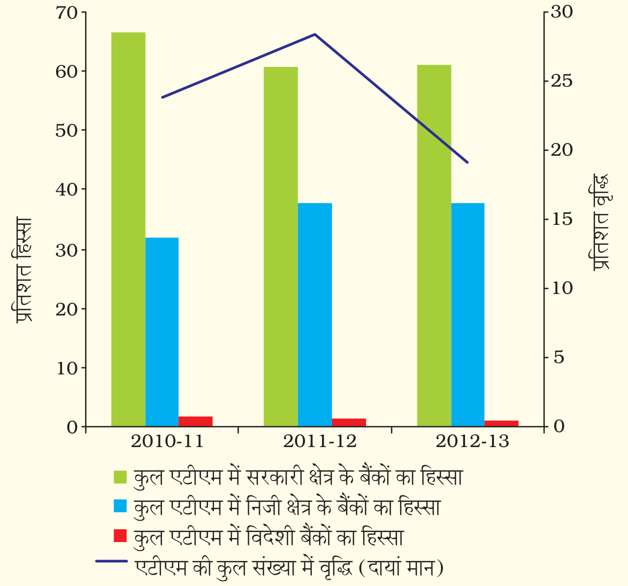

IV.23) । इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों का प्रसार अधिक तेजी से हुआ है (चार्ट IV.24)।

9.अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

एटीएम की संख्या में द्वि-अंकीय वृद्धि मुख्य रूप से निजी बैंकों के कारण हुई

4.47 2012-13 में देश भर में एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई और वर्ष के दौरान इनकी कुल संख्या 1,00,000 के पार पहुंचने के साथ ही इनमें द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज हुई (सारणी IV.27; चार्ट IV.25)। यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों के कारण हुई और एटीएम की कुल संख्या में उनकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई।

सारणी IV.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम
(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या
1	2	3	4	5
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**40,241**	**29,411**	**69,652**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	20,658	14,701	35,359
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	18,708	13,883	32,591
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**15,236**	**27,865**	**43,101**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4,054	3,512	7,566
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	11,182	24,353	35,535
III	**विदेशी बैंक**	**283**	**978**	**1,261**
IV	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)**	**55,760**	**58,254**	**1,14,014**

टिप्पणी: * आईडीबीआई बैंक लि.को छोडकर

ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में तेज वृद्धि, श्वेत लेबल एटीएम की शुरुआत के साथ इसमें अधिक तेज वृद्धि होने की संभावना

4.48 जहां एटीएम ग्राहकों को अधिक तेजी और लागत-प्रभावी तरीके से आधारभूत बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराने का नवीन उपाय हैं, वहीं इन एटीएमों में विशेषकर ऑफ-साइट एटीएम अधिक लागत-प्रभावी हैं क्योंकि ऐसे एटीएम बिना किसी बैंक शाखा के साजो-सामान के कार्य करते हैं। कुछ वर्षों से, ऑन-साइट एटीएम के मुकाबले ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में सापेक्षिक वृद्धि अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, 2012-13 तक, देश के एटीएमों की कुल संख्या में ऑफ-साइट एटीएम की हिस्सेदारी आधे से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.7; चार्ट IV.26)।

4.49 गैर-बैंकिंग संस्थाओं को एटीएम स्थापित करने और परिचालित करने की अनुमति देने की नीतिगत पहल के साथ ही, ऑफ-साइट एटीएम की संख्या में श्वेत लेवल एटीएम की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। अब तक 18 संस्थाओं ने श्वेत लेबल एटीएम स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन किया है, जिसमें से

चार्ट IV.26: ऑफ-साइट और ऑन-साइट एटीएम के प्रतिशत का हिस्सा

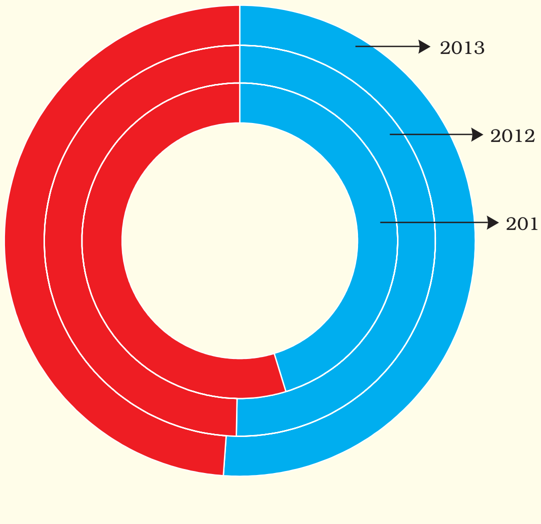

12 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से प्राधिकार दिया गया है और इनमें से एक को प्राधिकार-प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। तदनुसार, पहला श्वेत लेबल एटीएम महाराष्ट्र के थाणे जिले के चंद्रपाडा (टियर V कस्बा)में जून 2013 में शुरू हुआ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली के तहत चेक-आधारित लेनदेनों की कार्यक्षमता में वृद्धि

4.50 चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) एक स्थान से दूसरे स्थान तक चेक को भौतिक रू प से ले जाए बिना समाशोधन की गति में सुधार करने की ओर उठाया गया एक कदम है। इस प्रणाली के शुरू होने के बाद, विशेषकर नई दिल्ली और चेन्नै में इस प्रणाली के जरिए प्रोसेस होने वाले चेकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो इस प्रणाली की बढ़ती स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है (सारणी IV.28)। सीटीएस की परिधि में अधिक केंद्रों/क्षेत्रों को लाने के साथ इसका दायरा और विस्तृत हो गया है। इसके साथ ही इसकी मात्रा में आगे और वृद्धि होने से बड़ी संख्या में ग्राहकों को इस प्रणाली के फायदे मिलेंगे।

सारणी IV.28: चेक ट्रंकेशन प्रणाली के अंतर्गत प्रगति

मात्रा (मिलियन में)		मूल्य (रुपये बिलियन में)	
2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
180	275 (52.6)	15,104	21,732 (43.9)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत में घट-बढ़ दर्शाते हैं।

सारणी IV.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड
(मार्च के अंत में)

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या		बकाया डेबिट कार्डों की संख्या	
		2012	2013	2012	2013
	1	2	3	4	5
I	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**3.1**	**3.5**	**214.6**	**260.6**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	0.8	0.9	97.7	118.6
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह	2.2	2.6	112.0	136.4
II	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**9.7**	**11.1**	**60.0**	**67.3**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.04	0.04	13.9	15.4
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	9.6	11.1	46.0	51.9
III	**विदेशी बैंक**	**4.9**	**5.0**	**3.8**	**3.3**
IV	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)**	**17.7**	**19.5**	**278.4**	**331.2**

टिप्पणी: 1. *: आईडीबीआई बैंक लि.को छोडकर
2. आंकड़े हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण कुल में न जोड़े गए हों।

क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड इलेक्ट्रानिक मुद्रा का अधिक लोकप्रिय साधन है

4.51 अब तक, भारत में क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का अधिक लोकप्रिय साधन रहा है (सारणी IV.29; चार्ट IV.27)। जहां एक ओर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक डेबिट कार्ड

चार्ट IV.27: डेबिट और क्रेडिट कार्ड की प्रगति

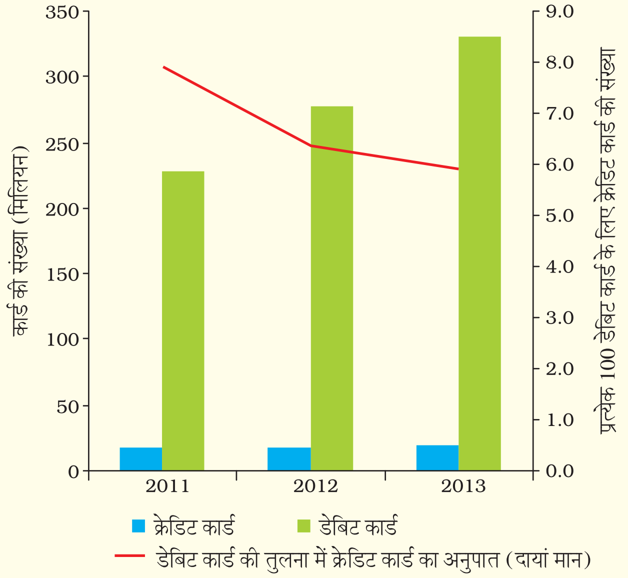

जारी करने में अग्रणी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के नए बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने में आगे बने हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और भुगतान में निरंतर वृद्धि

4.52 हाल के वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में सामान्य रूप से सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेन-देनों और विशेष रूप से डेबिट लेन-देनों की मात्रा एवं मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई हैं, 2012-13 में भी यह प्रवृत्ति जारी रही (सारणी IV.30)। इस प्रणाली के जरिए होने वाले लेन-देन की मात्रा के लिहाज से आरटीजीएस (बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली के लिए, 2,00,000 रुपए और इससे अधिक की राशि के ग्राहक और अंतर-बैंक दोनों लेन-देनों के लिए) और एनईएफटी (एक रिटेल प्रणाली) दोनों में निरंतर द्वि-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी IV. 30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य

(मात्रा मिलियन में, मूल्य बिलियन रुपयों में)

लेनदेन का प्रकार	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़	मूल्य		प्रतिशत घटबढ़
	2011-12	2012-13	2012-13	2011-12	2012-13	2012-13
ईसीएस क्रेडिट	121.5	122.2	0.6	1,838	1,771	-3.6
ईसीएस डेबिट	165	177	7.2	834	1,083	29.9
क्रेडिट कार्ड	320	397	23.9	966	1,230	27.3
डेबिट कार्ड	328	469	43.2	534	743	39.1
एनईएफटी	226	394	74.3	17,904	29,022	62.1
आरटीजीएस	55	69	24.5	5,39,308	6,76,841	25.5

टिप्पणी: आंकड़ों का पूर्णांकन मिलियन या बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घट-बढ़ हो सकता है ।

इस वृद्धि के बावजूद, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों के प्रयोग में आगे और सुधार की गुंजाइश है

4.53 भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विभिन्न तरीकों में वृद्धि होने के बावजूद, विश्व भर में विशेषकर उच्च आय वाले देशों में इस माध्यम से होने वाले लेन-देनों के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने में अभी इसे काफी लंबी दूरी तय करनी है। यह उल्लेखनीय है कि भुगतान के एक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन के प्रयोग में भारत का वैश्विक तौर पर एक स्थान है (सारणी IV.31)।

4.54 भुगतान/अंतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करने से बैंकों को परिचालन-लागत को कम करने में मदद मिल सकती है और इसका फायदा ग्राहकों को दिया जा सकता है। (बॉक्स IV.4)।

स्वचालित डेटा प्रवाह परियोजना के अंतर्गत बैंकों से विनियामक के लिए डेटा अंतरण में और सुधार

4.55 रिज़र्व बैंक द्वारा स्वचालित डेटा प्रवाह परियोजना की शुरुआत इस प्रयोजन से की गई थी कि बैंकों के आंतरिक प्रणाली से एक केंद्रीकृत प्रणाली तक और इसके बाद विनियामक तक बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सही रूप में एवं समय पर डेटा का अंतरण हो सके। स्वचालित डेटा प्रवाह में लगातार प्रगति हुई है और जून 2013 के अंत तक अधिकांश बैंकों की लगभग 80 प्रतिशत विवरणियां इस प्रणाली के अंतर्गत लाई गई हैं। इसके अलावा, बैंकों ने अनुपालन, बिजनेस और प्रौद्योगिकी के अधिकारियों को शामिल करके एक रिटर्न गवर्नेंस ग्रुप स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर दिया है।

सारणी IV.31: इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान करने में हुई प्रगति

निम्नलिखित का उपयोग कर रही 15 वर्ष और इससे अधिक आयु की आबादी का प्रतिशत	विश्व	उच्च आय वर्ग	उच्च मध्यम आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	*भारत*	निम्न मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग
क्रेडिट कार्ड	14.8	49.8	11.8	7.1	*1.8*	2.2	1.9
डेबिट कार्ड	30.4	61.4	38.6	24.8	*8.4*	10.1	7.4
भुगतान का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (तार और ऑनलाइन अंतरण)	14.5	55.2	8.2	5.3	*2.0*	2.3	1.9
मोबाइल फोन से बिल का भुगतान	2.0	-	1.7	1.8	*2.2*	2.0	2.6

टिप्पणी: डेटा 2011 के हैं।
स्रोत: वैश्विक फिंडेक्स (वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस), विश्व बैंक।

बॉक्स IV.4
बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवं लागत में कमी: एक परिप्रेक्ष्य

अध्ययन दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकी में उन्नयन के साथ ही सामान्यतया उत्पादन प्रक्रिया की वास्तविक लागत में कमी हो जाती है[15]। प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के दो प्रमुख लाभ हैं: (क) बैंक के परिचालन लागत में कमी (लागत में लाभ); (ख) एक ही नेटवर्क के तहत ग्राहकों के बीच अधिक प्रभावी लेन-देन उपलब्ध कराना (नेटवर्क प्रभाव)। इयादत एवं कोजैक (2005) ने अमेरिकी बैंकिंग सेक्टर के लिए 1992 और 2003 के बीच लागू की गई प्रौद्योगिकी और लाभप्रदता/लागत बचतों के बीच एक सकारात्मक अंतर्संबंध दर्शाया था। बर्गर (2003) ने भी नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अमेरिका में बैंकों के कार्यनिष्पादन और बैंकिंग उद्योग के सुदृढ़ीकरण में सुधार दर्शाया था। 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि प्रौद्योगिकी नवोन्मेष और आईटी में निवेश से कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। (राजपूत एवं गुप्ता, 2011)।

विश्व भर में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में तेजी से प्रगति हुई है और इसका प्रभाव, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों की कारोबारी रणनीति, ग्राहक सेवा और संगठनात्मक ढांचे में परिलक्षित हुआ है। इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम और मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में अपनाई गई नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी से बैंकिंग सेवाओं के सुपुदर्गी चैनल पर काफी अधिक प्रभाव पड़ा है। साथ-ही-साथ खुदरा भुगतान के क्षेत्र में कई सारी नवोन्मेषी गतिविधियां हुई हैं जिन्होंने प्रयोक्ताओं को अपनी पंसद के अनुरूप भुगतान के साधन चुनने के विकल्प को प्रभावित कर और भुगतान प्रक्रिया में काफी अधिक बदलाव लाकर खुदरा भुगतान बाजार पर असर डाला है।

खुदरा भुगतान में नवोन्मेष पर गठित भुगतान एवं निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) कार्यदल की रिपोर्ट (मई 2012) में सीपीएसएस और अन्य चुनिंदा देशों में हो रही नवोन्मेषी खुदरा भुगतान गतिविधियों के बारे में एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया है जिसमें विगत दशक में खुदरा भुगतान लिखतों/योजनाओं के संबध में हुई नवोन्मेषी गतिविधियां शामिल की गईं। पाए गए रुझानों के आधार पर, इस रिपोर्ट में ऐसे कई सारे बहिर्जात एवं अंतर्जात कारकों की पहचान की गई है जो खुदरा भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेष या इसमें अवरोध उत्पन्न करने के प्रेरक तत्व होते हैं। यह रिपोर्ट पूरे देश में होने वाले नवोन्मेष के प्रयोजन को दो मुख्य श्रेणियों में बांटती हैं "उन्नत कार्यदक्षता" एवं "उन्नत सुरक्षा"। उन्नत कार्यदक्षता को कई उप-श्रेणियों में बांटा गया है जैसे कम नकद प्रयोग, कम प्रोसेसिंग लागत, उन्न्त सुविधा और बैंकरहित/अल्प-बैंक क्षेत्रों का समावेशन। इस संबंध में, इस रिपोर्ट में एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति की पहचान की गई जिसके अनुसार वित्तीय समावेशन कई देशों में नवोन्मेष में एक प्रेरक शक्ति साबित हुआ है फिर चाहे यह सरकारी अधिदेश के चलते हुआ हो या फिर अदोहित बाजार में उपलब्ध हुए कारोबारी अवसर के कारण हुआ हो।

विकासशील देशों में जहां भुगतान प्रणाली का बुनियादी ढांचा कम विकसित होता है, वहां नवोन्मेषी भुगतान समाधान शुरू करने की अधिक संभावना होती है, और इसलिए वे खुदरा भुगतान लिखतों/बुनियादी संरचना को विकसित करने के लिए किए जाने वाले आम प्रयासों के मामले में कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाते हैं। 2007 में केन्या में शुरू की गई एम-पेसा प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष का ऐसा ही एक उदाहरण है। एम-पेसा के प्रयोक्ता अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किसी दूसरे मोबाइल फोन प्रयोक्ता को निधि अंतरित करने में कर सकते हैं। यह प्रणाली बहुत ही कम लागत पर सुरक्षित और तेजी से मुद्रा अंतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस प्रणाली से होने वाले फायदे को देखते हुए बड़े पैमाने पर इसे स्वीकार्यता मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग ने वित्तीय सेवाएं[16] मुहैया कराने की लागत को आश्चर्यजनक रूप से कम किया है। इस सर्वेक्षण में लगभग 85 प्रतिशत मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के मामले में लेन-देन की कम लागत रही। यह भी पाया गया कि मोबाइल-बैंकिंग ने ग्राहकों को दी जाने वाली आधारभूत बैंकिंग सेवाओं की लागत में, परंपरागत चैनल के जरिए आने वाली लागत के मुकाबले, तकरीबन 60 प्रतिशत की कमी की है।

केन्या में एम-पेसा के इतने सफल होने की मुख्य वजह यह रही कि वहां वित्तीय सेवाओं की बड़ी मांग है जिसकी पर्याप्त रूप से पूर्ति केन्याई, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर, भारत में बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच व्यापक है और यहां वित्तीय समावेशन के लिए बैंक-उन्मुख मॉडल पर फोकस किया गया है। इसके अलावा, भारत में वित्तीय समावेशन नीति के तहत जमा उत्पाद, किसान क्रेडिट कार्ड / जनरल क्रेडिट कार्ड के रूप में ओवरड्राफ्ट/आपातकालीन क्रेडिट सुविधा जैसे उपलब्ध कराए जा रहे कई सारे उत्पादों के मुकाबले, मोबाइल उन्मुख बैंकिंग के जरिए केवल प्रेषण संबंधी उत्पाद ही मुहैया कराए जा सकते हैं। तथापि वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोन की पहुंच को विस्तारित करने हेतु, कार्पोरेट को कारोबार संपर्की के रूप में नियुक्त करने की बैंकों को अनुमति दी जा रही है।

संदर्भ :

बर्गर, ए.एन. (2003), ''द इकॉनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेक्नॉलॉजिकल प्रोग्रेस: एवीडेंस फ्रॉम द बैंकिंग इन्डस्ट्री'', *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग*, वॉल्यूम 35।

बीआईएस (2012), *इनोवेशन्स इन रीटेल पेमेंट - ए रिपोर्ट*, सीपीएसएस,बासेल।

इयादात, एम. एवं एस. कोजैक (2005), ''द रोल ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी इन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट एफिशियंसी इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर'', *जर्नल ऑफ एकेडेमी ऑफ बिजनेस एंड इकॉनॉमिक्स*।

मुसारा, एम एवं एम फतोकी (2010), ''हैज टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन्स रिजल्टेड इन इन्क्रीज्ड एफिशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग्स फॉर बैंक्स कस्टमर?'', *अफ्रीकन जर्नल ऑफ बिज़नेस मैनजमेंट* , 4(9)।

जेंगा, ए.के. (2009), ''मोबाइल फोन बैंकिंग : यूसेज एक्सपिरियंसज इन केन्या'', <www.w3.org>।

राजपूत, एन. एवं एम. गुप्ता (2011), ''इम्पैक्ट ऑन आईटी ऑन इन्डियन कमर्शियल बैंकिंग इन्डस्ट्री: डीईए एनेलिसिस'', *ग्लोबल जर्नल ऑफ इन्टरप्राइज इन्फॉरमेशन सिस्टम*, 3(I)।

[15] उदाहरण के लिये देखें मसूरा एंड फतोकी (2010)।

[16] देखें जेंगा (2009)।

10.ग्राहक सेवा

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध कुल शिकायतों में टियर II शहरों की बढ़ती भागीदारी से परिलक्षित होता है कि ग्राहकों के बीच जागरुकता बढ़ी है

4.56 सभी 15 कार्यालयों में प्राप्त होने वाली कुल शिकायतों में टियर I शहरों (नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद) में स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों का हिस्सा आधे से अधिक है। तथापि, टियर II शहरों में बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि छोटे शहरों में ग्राहकों के बीच शिकायत निवारण प्रक्रिया के संबंध में जागरुकता बढ़ी है। (सारणी IV.32; चार्ट IV.28).

उचित व्यवहार संहिता और बीसीएसबीआई से संबंधित शिकायतों की महत्ता दर्शाती है कि ग्राहकों में जागरुकता बढ़ी है

4.57 यद्यपि एटीएम/क्रेडिट/डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतें अधिक हुईं, जिनकी संख्या और 2012-13 में प्राप्त हुईं कुल शिकायतों की एक-चौथाई थी, इसके बाद उचित व्यवहार संहिता और भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित संहिता के अननुपालन से संबंधित शिकायतें अगले स्थान पर थीं (परिशिष्ट सारणी IV.8; चार्ट IV.29)। हाल के वर्षों में इन संहिताओं से संबंधित शिकायतें बढ़ीं हैं, इससे यह परिलक्षित होता है कि ग्राहकों

सारणी IV.32: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार प्राप्त शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या		प्रतिशत में घटबढ़
	2011-12	2012-13	2012-13
अहमदाबाद	4,590	4,838	5.4
बंगलुरू	3,486	3,318	-4.8
भोपाल	5,953	4,920	-17.4
भुवनेश्वर	1,826	1,523	-16.6
चंडीगढ़	3,521	3,094	-12.1
चेन्नै	6,614	7,255	9.7
गुवाहाटी	708	807	14.0
हैदराबाद	5,167	4,303	-16.7
जयपुर	4,209	4,099	-2.6
कानपुर	9,633	9,012	-6.4
कोलकाता	4,838	4,388	-9.3
मुंबई	7,905	8,607	8.9
नई दिल्ली	9,180	9,444	2.9
पटना	2,718	2,785	2.5
तिरु वनंतपुरम	2,541	2,148	-15.5
कुल	**72,889**	**70,541**	**-3.2**

टिप्पणी: एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय ।

चार्ट IV.28: टियर I और II शहरों में शिकायतों की संख्या

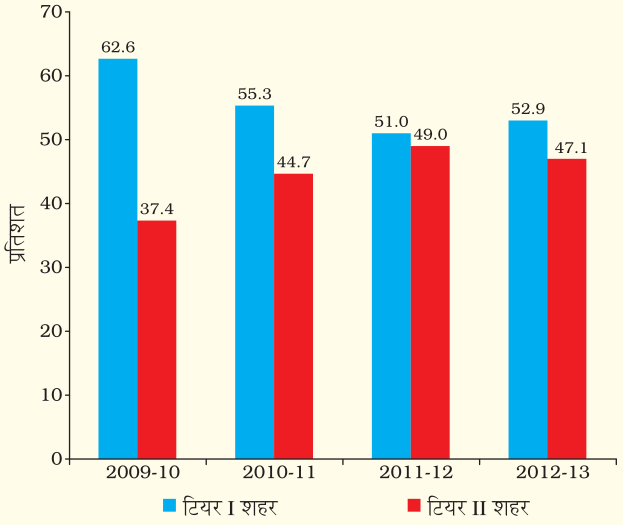

टिप्पणी: इसमें एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।

चार्ट IV.29: पांच प्रमुख प्रकार की शिकायतों का हिस्सा

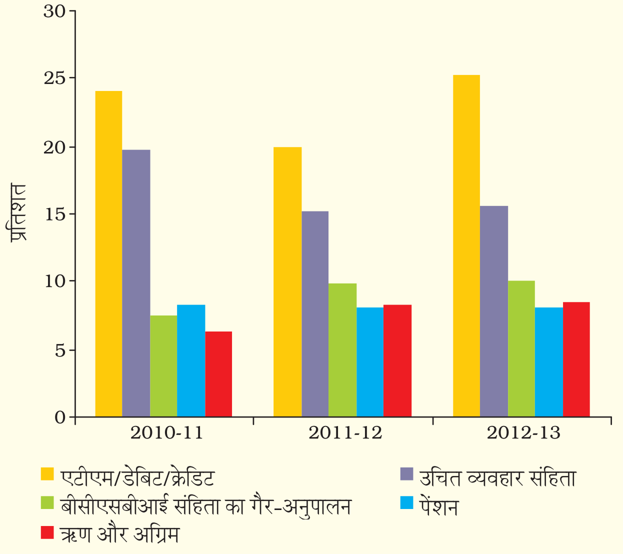

टिप्पणी: इसमें एससीबी, आरआरबी और यूसीबी शामिल हैं।

में इन संहिताओं और बैंकों द्वारा उनका अनुपालन किए जाने के प्रति जागरुकता बढ़ी है।

विदेशी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध प्रति बैंक शाखा/खाता को लेकर शिकायतें बढ़ी हैं

4.58 यद्यपि प्राप्त हुईं कुल शिकायतों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, लेकिन यदि इसे बैंक शाखा तथा खाता (जमा+ऋण खाता) की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो विदेशी बैंकों के संबंध में शिकायतों की संख्या सबसे अधिक रही और इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों का क्रम था (चार्ट IV.30)। 2012-13 में विदेशी बैंकों की प्रति 100 बैंक शाखा 1,543 शिकायतें हुईं जो सभी बैंक समूहों में सबसे अधिक थीं।

11. वित्तीय समावेशन

तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना के पूरा होने के बाद उल्लेखनीय प्रगति हुई

4.59 वर्ष 2010 में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफ़आईपी) को अपनाया जिसमें तीन वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु स्व-निर्धारित लक्ष्य तय किए गए। 2013 में बैंकों ने इस योजना के तहत तीन वर्ष पूरे किए। पिछले तीन वर्ष की गतिविधियों का जायजा लेने पर ज्ञात हुआ कि वित्तीय समावेशन के संबंध में काफी प्रगति हुई है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं (सारणी IV.33):

- 2,000 से अधिक आबादी वाले लगभग सभी चिह्नित बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- 2,000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है; 2,000 से कम आबादी वाले ऐसे गांवों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिन्हें 2012 और 2013 के बीच बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए। (चार्ट IV.31).
- गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में कारोबार संपर्की की प्रमुख भूमिका - 2,000 से अधिक/कम आबादी वाले गांवों में शाखा, कारोबार संपर्की और अन्य (आईसीटी-आधारित) माध्यमों के जरिए बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इन तीनों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में बैंक शाखा खोलने की अपेक्षा कारोबार संपर्की का प्रभुत्व रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में कारोबार संपर्की महत्त्वपूर्ण माध्यम रहे हैं।

4.60 डेटा-आधारित इन निष्कर्षों के अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के प्रयासों के जमीनी स्तर पर हुए प्रभाव के बारे में किए गए सर्वेक्षण से कुछ उपयोगी जानकारी भी प्राप्त हुई है (बॉक्स IV.5)।

चार्ट IV.30: 2012-13 के दौरान प्रत्येक बैंक शाखाओं/खातों की शिकायतों की संख्या

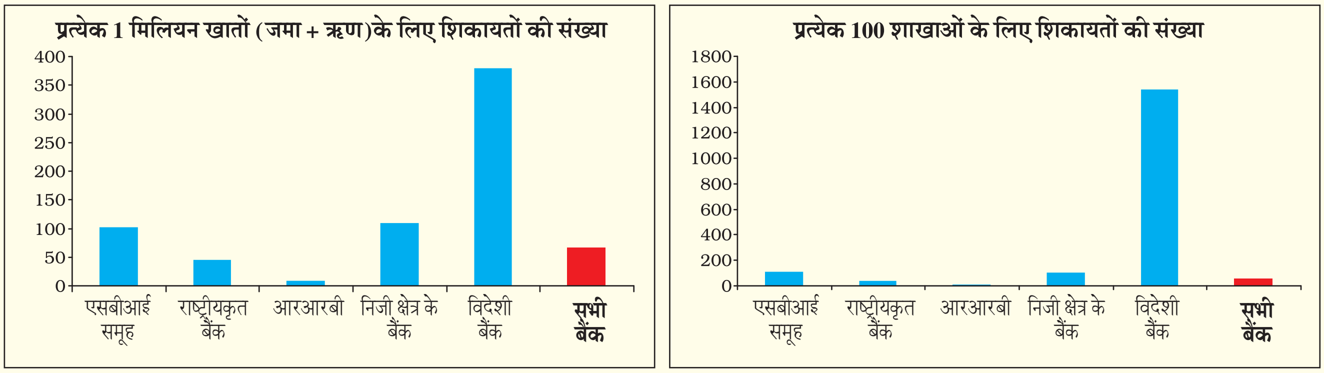

टिप्पणी: प्रति खाता शिकायतों की संख्या 2011-12 की हैं क्योंकि 2012-13 के खातों की संख्या के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं हैं।
स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यलयों से प्राप्त डेटा और *भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय विवरणी, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों और ऋणों पर त्रैमासिक सांख्यिकी।*

सारणी IV.33: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सं.	घटबढ़	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	मार्च-13	पूर्ण परिवर्तन (2010-2013)	प्रतिशत घटबढ (2010-2013)
1	2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केंद्र	37,949	66,605	1,12,288	1,19,453	81,504	214.8
2	2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केंद्र	29,745	49,603	69,465	1,49,001	1,19,256	400.9
3	गांवों में बैंकिंग केंद्र - शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	7,459	22.3
4	गांवों में बैंकिंग केंद्र - बीसी	34,174	80,802	1,41,136	2,21,341	1,87,167	547.7
5	गांवों में बैंकिंग केंद्र -अन्य माध्यम	142	595	3,146	6,276	6,134	4,319.7
6	गांवों में बैंकिंग केंद्र - कुल	67,694	1,16,208	1,81,753	2,68,454	2,00,760	296.6
7	बीसी के जरिए शामिल किए गए शहरी इलाके	447	3,771	5,891	27,143	26,696	5,972.3
8	शाखाओं (मिलियन में संख्या) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	60	73	81	101	41	67.5
9	शाखाओं (राशि रुपये बिलियन में) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	44	58	110	165	120	271.5
10	बीसी (मिलियन में संख्या) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	13	32	57	81	68	512.4
11	बीसी (राशि रुपये बिलियन में) के जरिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)	11	18	11	18	8	70.4
12	कुल बीएसबीडीए की कुल राशि (मिलियन में)	73	105	139	182	109	147.9
13	बीएसबीडीए की कुल राशि (बिलियन में)	55	76	120	183	128	232.5
14	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता के माध्यम से प्राप्त ओडी सुविधा (मिलियन में संख्या)	0.2	1	3	4	4	2,094.4
15	बुनियादी बचत बैंक जमा खाता के माध्यम से प्राप्त ओडी सुविधा (राशि रुपये बिलियन में)	0.1	0.3	1	2	1.5	1,450.0
16	केसीसी - मिलियन में कुल संख्या	24	27	30	34	9	39.0
17	केसीसी - कुल (राशि रुपये बिलियन में)	1,240	1,600	2,068	2,623	1,383	111.5
18	जीसीसी - कुल (मिलियन में संख्या)	1	2	2	4	2	161.2
19	जीसीसी - कुल (राशि रुपये बिलियन में)	35	35	42	76	41	117.4
20	आईसीटी खाता-बीसी-कुल लेनदेन- (मिलियन में संख्या)	27	84	156	250	224	844.4
21	आईसीटी खाता-बीसी-कुल लेनदेन- (राशि रुपये बिलियन में)	7	58	97	234	227	3,279.8

टिप्पणी: पूर्ण और प्रतिशत घटबढ़ में थोडा अंतर हो सकता है क्योंकि संख्याओं का मिलियन/बिलियन में पूर्णांकन किया गया है।
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक।

चार्ट IV.31: जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत गांवों में बैंकिंग केंद्रों की प्रगति

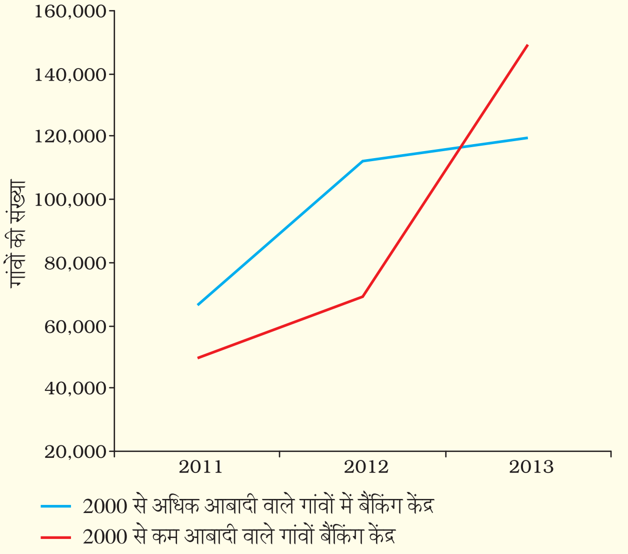

नई खोली गई अधिकतम शाखाएं टियर 5 एवं 6 / ग्रामीण केंद्रों में थीं

4.61 विगत तीन वर्षों के दौरान, टियर 5 एवं 6 केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। 2012-13 में खोली गई कुल शाखाओं में लगभग 41 प्रतिशत शाखाएं सम्मिलित रूप से इन दो केंद्रों में खोली गईं। सम्मिलित रूप से ये दोनों केंद्र ऐसे केंद्र हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है और ये देश में "ग्रामीण" केंद्र को दर्शाते हैं। (सारणी IV.34).

सभी क्षेत्रों में बैंकरहित केंद्रों में खोली गई नई शाखाओं का बढ़ता हुआ अनुपात

4.62 2012-13 में नई खोली गई शाखाओं की कुल संख्या में से 25 प्रतिशत बैंकरहित केंद्रों में खोली गईं; शेष 75 प्रतिशत

बॉक्स IV.5
वित्तीय समावेशन का एक सर्वेक्षण-आधारित विश्लेषण

भारत की आर्थिक नीति में आजादी के समय से ही वित्तीय समावेशन एक उद्देश्य के रूप में अंगीकृत रहा है। तथापि, वर्ष 2005 से यह रिज़र्व बैंक के स्पष्ट नीतिगत प्रयास के रूप में सामने आया है। विशेषकर 2005 के बाद व्यापक वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा कई सारी नीतिगत पहलें की गई हैं। इस पृष्ठभूमि के बीच, बैंकिंग सेवाओं की मांग और वित्तीय समावेशन नीति के जमीनी स्तर पर प्रभाव के बारे में अक्सर जानकारी का अभाव महसूस किया जा रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र अर्थात् मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 14 जिलों में सर्वेक्षण किए गए। इस सर्वेक्षण में संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया और 8,246 परिवारों एवं कुल मिलाकर 34,149 लोगों को इसमें शामिल किया गया।

अधिकांश गांवों में कृषि मुख्य व्यवसाय था। इन गांवों से बैंकिंग आउटलेट की औसत दूरी 10 किलोमीटर थी। सर्वेक्षण के नमूने में पुरुष एवं महिलाएं लगभग बराबर की संख्या में शामिल थे।

इस सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे सारणी में दिए गए हैं:

इस अध्ययन से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर आए हैं जो महत्त्वपूर्ण नीतिगत इन्पुट उपलब्ध कराते हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि बैंकिंग सेवाओं के प्रति वित्तीय जागरुकता है और साथ ही इसकी मांग भी है। इसलिए यदि बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है तो इसके प्रयोग में सुधार होगा। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के मार्ग में अवरोध के मुख्य कारक बैंकिंग आउटलेट की अनुपलब्धता और वर्तमान बैंकिंग आउटलेट की लंबी दूरी है। आधारभूत बैंकिंग उत्पादों, जैसे जमा और क्रेडिट का उपयोग काफी विस्तृत है लेकिन ईबीटी एवं ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अपर्याप्त जागरु कता के कारण इन सुविधाओं का प्रयोग कम है। वृहत् समावेशन में निम्नलिखित शामिल होंगे

- गांवों में या उनके नजदीक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना।
- इन उत्पादों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद विशिष्ट जागरूकता उत्पन्न करना।
- महिलाओं और अपेक्षाकृत कम आय वाले ग्रामीण परिवारों में बैंकिंग सेवाओं के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करना।
- उधारकर्ता के आय की स्थिति से जुड़े उत्पादों का सृजन और तदनुसार उन्हें बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना।

सारणी: अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

	मानदंड	निष्कर्ष
1	वित्तीय जागरुकता- बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरुकता	**जागरुकता का उचित स्तर** - 76 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से परिचित थे। **लिंग** - आनुपातिक रूप से पुरुषों में जागरुकता अधिक थी। **उम्र** - उम्र एवं वित्तीय जागरुकता के स्तर के बीच कोई निश्चित संबध नहीं था। 18-25 की आयु वर्ग वाले लगभग 91 प्रतिशत लोग वित्तीय रूप से जागरूक थे। 26-60 वर्ष की आयु वर्ग में केवल 74 प्रतिशत जागरूक थे लेकिन 60 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग में 82 प्रतिशत लोग वित्तीय रूप से जागरूक थे। **आय** - आय और वित्तीय जागरुकता के स्तर के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं था। 50,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 89 प्रतिशत ग्रामीण जागरूक थे। 0.1-0.3 मिलियन रुपए के आय वर्ग में 42 प्रतिशत जागरूक थे, जबकि 0.3 मिलियन रुपए और इससे अधिक आय वर्ग में सभी वित्तीय रूप से जागरूक थे।
2	**बैंकिंग उत्पादों का प्रयोग**	
	क बचत खाता	**बचत खातों का उपयोग सबसे अधिक था** - लगभग 74 प्रतिशत ग्रामीणों के पास बचत खाता था।
	ख क्रेडिट उत्पाद	**क्रेडिट उत्पादों का प्रयोग दूसरे स्थान पर था** - लगभग 34 प्रतिशत ग्रामीण ऋण सुविधाओं (किसान क्रेडिट कार्ड / सामान्य क्रेडिट कार्ड सहित) का उपयोग कर रहे थे ।
	ग प्रेषण	**इसके बाद प्रेषण सुविधाओं का स्थान था** - लगभग 24 प्रतिशत ग्रामीण प्रेषण सुविधा का उपयोग कर रहे थे।
	घ बचत खाता में ओवरड्राफ्ट	**ग्रामीणों के बीच ओवरड्राफ्ट का प्रयोग सीमित था** - केवल 12 प्रतिशत ग्रामीण बचत खाता में ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग कर रहे थे।
	ङ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी)	**ईबीटी का प्रयोग भी सीमित था** - केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण ही ईबीटी सुविधा का उपयोग कर रहे थे।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सारणी IV.34: खोली गईं नई बैंक शाखाओं का टियर-वार ब्यौरा

टियर	2010-11	2011-12	2012-13P
टियर 1	1,942	2,235	1,752
टियर 2	449	642	791
टियर 3	1,167	1,241	1,006
टियर 4	663	823	727
टियर 5	580	979	1,114
टियर 6	877	1,553	1,823
कुल	**5,678**	**7,473**	**7,213**

अ - अनंतिम

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

शाखाएं ऐसे केंद्रों में खोली गईं जहां बैंक पहले से मौजूद थे। तथापि यह उल्लेखनीय है कि बैंकरहित केंद्रों में खोली गई शाखाओं के अनुपात में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है (चार्ट IV.32) । यह वृद्धि देश के सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है।

बैंकिंग पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता कम होने के संकेत

4.63 बैंकरहित केंद्रों में शाखाओं की बढ़ती पैठ के चलते मुख्य रूप से इसका फायदा ऐसे क्षेत्रों को हुआ जहां बैंकों की पैठ कम थी,

चार्ट IV.32: क्षेत्रवार, बैंक रहित केंद्रों में खोली गईं नई शाखाओं का हिस्सा

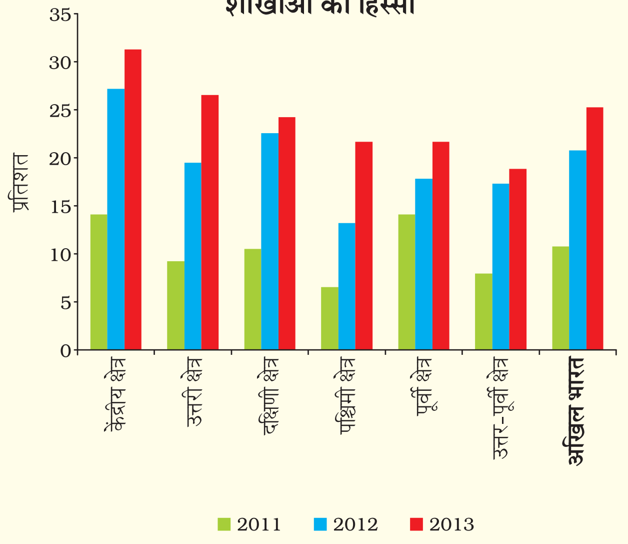

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट IV.33: बैंकिंग के फैलाव के संदर्भ में क्षेत्रीय अंतर

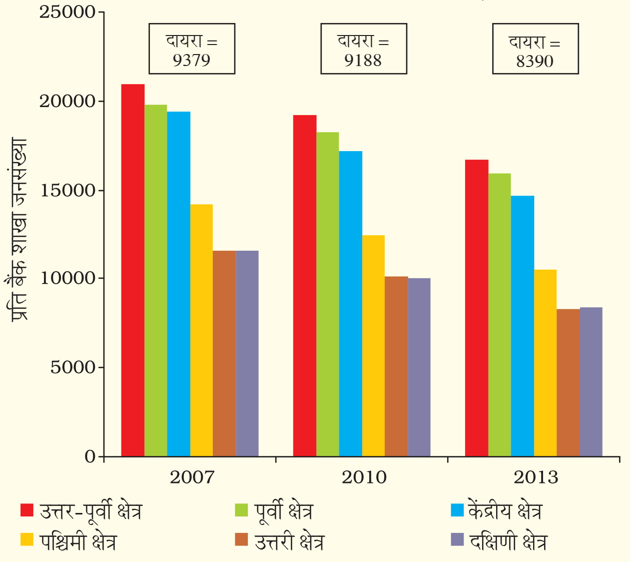

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जनगणना डेटाबेस।

अर्थात् पूर्वोत्तर, पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र। परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में बैंकिंग पहुंच के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानता कम हुई है जैसाकि प्रति बैंक शाखा आबादी के दायरे (अधिकतम-न्यूनतम)में हुई निरंतर गिरावट से परिलक्षित होता है। (चार्ट IV.33)।

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में खोले गए एटीएम की संख्या में वृद्धि

4.64 यद्यपि देश में, एटीएम की कुल संख्या में 65 प्रतिशत से अधिक एटीएम शहरी एवं महानगर केंद्रों में हैं, तथापि हाल के वर्षों में ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई है। (सारणी IV.35; चार्ट IV.34).

स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह की दोहरी व्यवस्था के जरिए माइक्रोफाइनेंस की सुपुर्दगी में निरंतर प्रगति

4.65 पूर्व की भांति, स्वयं सहायता समूहों के जरिए माइक्रोफाइनेंस की सुपुर्दगी में निरंतर प्रगति हुई। संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) सामान्य रूप से छोटे किसानों और विशेष रूप से पट्टेदार किसानों की जीविका गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक सफल गैर-संपार्श्विक

सारणी IV.35 : विभिन्न केंन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या

(मार्च 2012 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**8,552**	**18,445**	**22,518**	**20,137**	**69,652**
	(12.3)	**(26.5)**	**(32.3)**	**(28.9)**	**(100.0)**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	4,406	8,283	10,873	11,797	35,359
	(12.5)	(23.4)	(30.8)	(33.4)	(100.0)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	4,053	9,847	10,912	7,779	32,591
	(12.4)	(30.2)	(33.5)	(23.9)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	**2,982**	**9,244**	**13,349**	**17,526**	**43,101**
	(6.9)	**(21.4)**	**(31.0)**	**(40.7)**	**(100.0)**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	768	2,760	2,354	1,684	7,566
	(10.2)	(36.5)	(31.1)	(22.3)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2,214	6,484	10,995	15,842	35,535
	(6.2)	(18.2)	(30.9)	(44.6)	(100.0)
विदेशी बैंक	**30**	**21**	**244**	**966**	**1,261**
	(2.4)	**(1.7)**	**(19.3)**	**(76.6)**	**(100.0)**
कुल	**11,564**	**27,710**	**36,111**	**38,629**	**1,14,014**
	(10.1)	**(24.3)**	**(31.7)**	**(33.9)**	**(100.0)**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	**33.9**	**22.2**	**16.5**	**15.8**	**19.2**

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं ।
* आईडीबीआई बैंक लि. को छोड़कर।

चार्ट IV.34: क्षेत्रवार एटीएम की संख्या

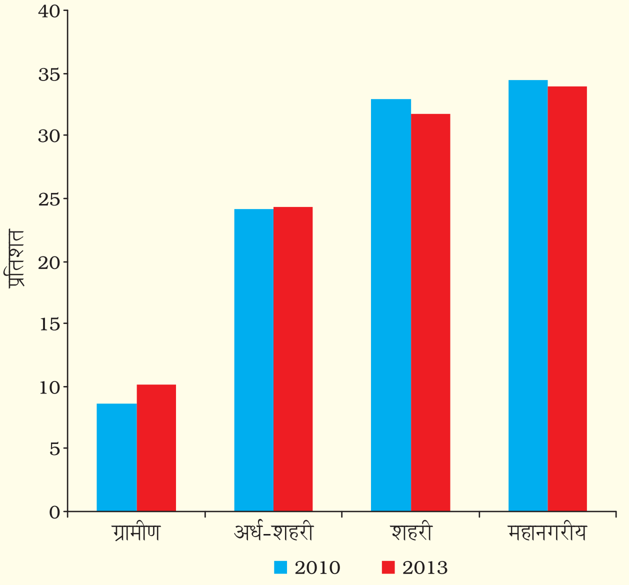

क्रेडिट लिखत के रूप में उभरा है। स्वयं सहायता समूह के बीच लिंकेज माइक्रोफाइनेंस का अधिक प्रभावी माध्यम बना हुआ है और वर्ष 2012-13 में बैंकों ने एक मिलियन से अधिक स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण किया। (सारणी IV.36).

सारणी IV.36: माइक्रो फाइनेन्स कार्यक्रमों की प्रगति

(मार्च के अंत में)

मद	स्वयं सहायता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (बिलियन रुपये में)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13P	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.6	1.2	1.2	1.2	145	145	165	206
	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(22)	(25)	(26)	(22)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.9	4.8	4.4	4.5	280	312	363	394
	(1.3)	(1.3)	(1.2)	(1.2)	(63)	(78)	(81)	(86)
बैंकों के पास बचतें	7.0	7.5	8.0	7.3	62	70	66	82
	(1.7)	(2.0)	(2.1)	(2.1)	(13)	(18)	(14)	(18)
	माइक्रो फाइनेन्स संस्थाएं							
	संख्या				राशि (बिलियन रुपये में)			
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	691	469	465	426	81	76	53	78
बैंकों के पास बकाया उधार	1,513	2,176	1,960	2,042	101	107	115	144
	संयुक्त देयता समूह							
	संख्या (मिलियन में)				राशि (बिलियन रुपये में)			
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	-	0.09	0.19	0.20	-	7	17	18

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) संबंधी ब्यौरा दर्शाते हैं। अ: अनंतिम आकड़ें
स्रोत: नाबार्ड ।

बैंकों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की संख्या में तीव्र गिरावट

4.66 इसके विपरीत, हाल के वर्षों में, बैंकों द्वारा वित्तपोषित माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की संख्या में तीव्र गिरावट हुई है। अंशतः, इसकी वजह आंध्र प्रदेश में कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की परिचालन संबंधी चिंताएं और हाल में इन चिंताओं के परिणास्वरूप उठाए गए विनियामक कदम हो सकते हैं (सारणी IV.36)।

12. स्थानीय क्षेत्र बैंक

स्थानीय क्षेत्र बैंक की लाभप्रदता कायम रही

4.67 आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर स्थानीय क्षेत्र बैंकों की समग्र स्तर पर लाभप्रदता अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से काफी ज्यादा है (सारणी IV.37 सारणी IV.8 के साथ पठित)। लेकिन, निवल ब्याज मार्जिन के अधार पर दक्षता की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्र बैंकों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से पिछड़ने की प्रवृत्ति दिखाई दी।

स्थानीय क्षेत्र बैंकों का परिचालन एवं भावी में विस्तार : समीक्षा की आवश्यकता

4.68 स्थानीय क्षेत्र बैंक लाभदायक होते हुए भी, उनके परिचालन और भावी विस्तार के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। पहला, स्थानीय क्षेत्र बैंक पूरी बैंकिंग प्रणाली का बहुत छोटा भाग हैं (अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्ति की 0.02 प्रतिशत), जिसमें चार में से एक स्थानीय क्षेत्र बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक (सभी चार स्थानीय क्षेत्र बैंकों की कुल आस्ति का 72 प्रतिशत) में बैंकिंग व्यापार का संकेद्रण है (सारणी IV.38) । दूसरा, 2002 के समीक्षा समूह, जिसने स्थानीय क्षेत्र बैंकों की गतिविधियों की जांच की थी, की सिफारिशों के विपरीत, कैपिटल लोकल एरिया बैंक को छोड़कर कोई भी स्थानीय क्षेत्र बैंक वित्तीय दृढ़ता सुधारने के लिए अपनी निवल मालियत 250 मिलियन रुपए तक बढ़ा नहीं सका। इन बाधाओं के होते हुए भी, इन संस्थाओं में लघु-स्तरीय बैंकिंग संस्था की असीम संभावनाएं हैं जिन्हें आगे चलकर बड़े पैमाने पर भी आजमाया जा

सारणी IV.37 : स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

	राशि		प्रतिशत घटबढ़	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**1.5**	**1.8**	**0.3**	**18.7**
i) ब्याज आय	1.4	1.6	0.3	19.9
ii) अन्य आय	0.2	0.2	0.0	8.7
ख. खर्च (i+ii+iii)	**1.3**	**1.6**	**0.2**	**17.4**
i) व्यय किया गया ब्याज	0.8	1.0	0.2	25.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.1	0.1	0.0	-20.3
iii) परिचालन व्यय	0.4	0.5	0.1	15.9
जिसमें से: वेतन बिल	0.2	0.3	0.0	23.8
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ / हानि	**0.3**	**0.4**	**0.0**	**7.1**
ii) निवल लाभ / हानि	**0.2**	**0.2**	**0.1**	**27.7**
घ. अंतर (निवल ब्याज आय)	**0.6**	**0.7**	**0.1**	**13.2**
ङ. कुल आस्तियां	**13.6**	**15.8**	**2.1**	**15.6**
च. वित्तीय अनुपात @				
i) परिचालन लाभ	2.6	2.4	-	-
ii) निवल लाभ	1.5	1.6	-	-
iii) आय	12.3	12.3	-	-
iv) ब्याज आय	11.0	11.1	-	-
v) अन्य आय	1.3	1.2	-	-
vi) व्यय	10.8	10.7	-	-
vii) व्यय किया गया ब्याज	6.2	6.5	-	-
viii) परिचालन व्यय	3.6	3.5	-	-
ix) वेतन बिल	1.7	1.7	-	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.1	0.8	-	-
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	4.9	4.6	-	-

टिप्पणी : आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है ।
@ कुल औसत आस्तियों की तुलना में अनुपात।
स्रोत: ऑफ -साइट विवरणियों पर आधारित।

सारणी IV.38: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफ़ाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि बिलियन रुपये में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	9.67 (71.0)	11.40 (72.3)	8.20 (73.8)	9.78 (74.8)	5.18 (67.2)	6.06 (67.1)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.93 (14.2)	2.21 (14.0)	1.51 (13.6)	1.74 (13.3)	1.26 (16.4)	1.56 (17.3)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.35 (9.9)	1.44 (9.1)	1.00 (9.0)	1.15 (8.8)	0.84 (10.9)	0.96 (10.6)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.68 (5.0)	0.72 (4.5)	0.39 (3.5)	0.41 (3.1)	0.43 (5.6)	0.45 (5.0)
स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंक	**13.63 (100.0)**	**15.76 (100.0)**	**11.10 (100.0)**	**13.07 (100.0)**	**7.71 (100.0)**	**9.03 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
स्रोत : ऑफ साइट (घरेलू) विवरणियों पर आधारित।

सकता है। इसलिए रिज़र्व के डिस्कशन पेपर "बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया : दि वे फॉरवेर्ड" में यह सिफारिश की गई है कि स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की दृष्टि से निजी क्षेत्र में ऐसे छोटे बैंक अधिक संख्या में बनाए जाएं। ऐसे बैंक अपने परिचालन के सीमित क्षेत्र तथा आपस में कम वित्तीय संबंधों के कारण प्रणालीगत स्थिरता के लिए कम जोखिम पैदा करते हैं। तथापि, इन बैंकों के डूबने की उच्च संभाव्यता से निपटने के लिए उचित कॉरपोरेट गवर्नेंस और सशक्त समाधान फ्रेमवर्क बनाने के बाद ही ऐसे बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

9 प्रतिशत सीआरएआर की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने के लिए पुन:पूंजीकरण का कार्य प्रगति पर है

4.69 समिति (अध्यक्ष : डॉ.के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों के फलस्वरूप, मार्च 2012 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी स्तर को बढ़ाते हुए, उनको 9 प्रतिशत सीआरएआर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु इन संस्थाओं के पुन:पूंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। समिति ने अनुमान लगाया है कि इस मानदंड की प्राप्ति के लिए 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 22 बिलियन रुपए तक की पूंजी डालने की आवश्यकता है।

4.70 मार्च 2013 तक, पुन:पूंजीकरण के लिए चुने गए 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्णत: और 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अंशत: पुन:पूंजीकृत किया गया है। शेष तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुन:पूंजीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। भारत सरकार ने संपूर्ण कार्यप्रणाली को पूरा करने की अवधि को मार्च 2014 तक बढ़ा दिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन का एक नया चरण शुरू हो गया

4.71 अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के दो व्यापक चरण थे। पहले चरण में (सितंबर 2005- मार्च 2010), एक राज्य में एक ही प्रायोजक बैंक के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित कर उनकी संख्या को 196 से घटाकर 82 कर दिया गया है। अक्तूबर 2012 से चल रहे दूसरे चरण में, राज्य के भीतर अलग-अलग प्रायोजक बैंक के अधीनस्थ तथा भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन इस प्रकार किया गया ताकि मझौले आकार वाले राज्यों में सिर्फ एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा बड़े आकार वाले राज्यों में दो/तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हों। इस वर्तमान चरण में, 9 राज्यों के 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित कर 13 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैक बनाए गए जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या घटाकर 64 हो गई है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलनपत्र में उच्चतर संवृद्धि

4.72 वर्ष के दौरान,जहां अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन पत्र में संकुचन हुआ, वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलनपत्र में विस्तार हुआ (सारणी IV.39) । फिर भी, वर्ष के दौरान ऋण, जो तुलन

सारणी IV.39: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
		2012	2013अ	2011-12	2012-13अ
1	शेयर पूंजी	2	2	0.0	0.0
2	आरक्षित निधियां	113	132	17.7	17.0
3	शेयर पूंजी जमा	50	57	22.7	14.6
4	जमाराशियां	1,863	2,085	12.1	11.9
	4.1 चालू	104	115	12.8	11.2
	4.2 बचत	986	1,069	8.2	8.4
	4.3 अवधि	774	900	17.4	16.3
5	से उधार	303	379	14.3	25.1
	5.1 नाबार्ड	211	297	31.7	40.9
	5.2 प्रायोजक बैंक	88	74	-10.4	-16.0
	5.3 अन्य	4	8	-199.4	97.6
6	अन्य देयताएं	94	103	7.4	9.0
कुल देयताएं / आस्तियां		**2,425**	**2,758**	**12.6**	**13.7**
7	नकदी	23	22	6.3	-2.3
8	आरबीआई के पास शेष	88	83	-10.2	-6.7
9	अन्य बैंक शेष	478	619	5.9	29.3
10	निवेश	602	620	11.2	3.0
11	ऋण और अग्रिम (निवल)	1,130	1,309	19.3	15.8
12	अचल आस्तियां	6.7	7.3	46.4	9.4
13	अन्य आस्तियां #	96	98	8.9	1.5

टिप्पणी: 1. #: संचित हानि सहित ।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।
3. अ: अनंतिम

स्रोत: नाबार्ड ।

पत्र की आस्तियों के सबसे बड़ा भाग हैं तथा जमाराशियां, जो तुलन पत्र की देयताओं की सबसे बड़ी भाग हैं, दोनों की संवृद्धि

सारणी IV.40: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम

(राशि बिलियन रुपये में)

क्र. सं.	प्रयोजन/ मार्च को समाप्त	2012	2013अ
1	2	3	4
I	**कृषि (i से iii)**	**638**	**752**
	कुल बकाया ऋण की तुलना में प्रतिशत	*54.8*	*53.8*
	i अल्पकालिक ऋण (फसल ऋण)	466	551
	ii मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	172	201
	iii अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
II	**कृषि से इतर (i से iv)**	**526**	**645**
	कुल बकाया ऋण की तुलना में प्रतिशत	*45.2*	*46.2*
	i ग्रामीण कारीगर, आदि	10	11
	ii अन्य उद्योग	37	42
	iii खुदरा व्यापार, आदि	58	62
	iv अन्य प्रयोजन	420	530
कुल (I+II)		**1,164**	**1,397**
	ज्ञापन मदें:		
(क)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	955	1,143
(ख)	गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	208	253
	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा (कुल की तुलना में प्रतिशत)	*82.1*	*81.8*

अ: अनंतिम

स्रोत : नाबार्ड ।

सारणी IV.41: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

क्रम सं.	मद	राशि		प्रतिशत घटबढ़	
		2011-12 (82)	2012-13* (64)	2011-12	2012-13*
1	2	3	4	5	6
क	**आय (i + ii)**	**200**	**208**	**23.6**	**3.7**
	i ब्याज आय	189	196	24.3	3.3
	ii अन्य आय	11	12	12.3	11.0
ख	**व्यय (i + ii + iii)**	**182**	**186**	**24.7**	**2.3**
	i ब्याज व्यय	112	118	30.5	4.8
	ii परिचालन व्यय	55	54	12.3	-2.1
	जिसमें से: वेतन बिल	40	39	4.0	-2.6
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	14.5	14.3	35.2	-1.0
ग	**लाभ**				
	i परिचालन लाभ	33	36	21.7	9.8
	ii निवल लाभ	19	22	14.4	17.2
घ	**कुल आस्तियां**	**2,425**	**2,758**	**12.6**	**13.7**
ङ	**वित्तीय अनुपात #**				
	i परिचालन लाभ	1.4	1.4		
	ii निवल लाभ	0.8	0.8		
	iii आय (क+ख)	8.8	8.0		
	(क) ब्याज आय	8.3	7.5		
	(ख) अन्य आय	0.5	0.5		
	iv व्यय (क+ख+ग)	7.9	7.2		
	(क) व्यय किया गया ब्याज	4.9	4.5		
	(ख)परिचालन व्यय	2.4	2.1		
	जिसमें से : वेतन बिल	1.7	1.5		
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.6		

*: वर्ष का लेखापरीक्षित डेटा के रूप में अनंतिम डेटा (त्रिपुरा जी बी को छोड़कर) अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है।

टिप्पणी : 1. #: वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के हैं।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन बिलियन रुपये में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड और रिज़र्व बैंक।

में धीमी गिरावट आई (सारणी IV.39; सारणी IV.40)। ऋण के कम उठाव (आफ-टेक) के बावजूद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पिछले वर्ष की तरह अपनी आस्तियों पर प्रतिलाभ को बनाए रख सके (सारणी IV.41)।

14. समग्र मूल्यांकन

4.73 2012-13 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन और कार्य-निष्पादन पर मोटे तौर पर निम्न का प्रभाव पड़ा (i) घरेलू अर्थव्यवस्था की लगातार मंदी के साथ-साथ धीमा वैश्विक सुधार, (ii) ब्याज दरों में कमी, (iii) उच्च विदेशी संस्थागत निवेशों के अंतर्वाह जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाज़ार में एक सामान्य तेजी दिखी। इन समष्टि आर्थिक गतिविधियों के अलावा, अध्याय III में प्रतिपादित, अन्यों बातों के साथ-साथ, पुनर्संरचित

अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों की परिभाषा और लक्ष्य में परिवर्तन जैसी कई नीतिगत पहलों सहित हाल के दौरान शुरू किए गए कई नीतिगत उपायों ने भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन को प्रभावित किया है। 2012 -13 के दौरान अनुसूचित वणिज्य बैंकों के परिचालन की मुख्य विशेषताओं का सारांश निम्न प्रकार है:

बैंकिंग क्षेत्र की समग्र संवृद्धि में मंदी, विशेषत: बैंक ऋण में

4.74 2012-13 के दौरान भारतीय बैंकों के तुलन-पत्र और तुलन-पत्रेतर परिचालनों में लगातार दूसरे साल मंदी रही। खुदरा ऋण में तेजी बनी रहने के बावजूद ऋण संवृद्धि में समग्र रूप से मंदी रही। यह मंदी स्टेट बैंक समूह को छोडकर सभी बैंक समूहों में फैली हुई थी।

ऋण के कम उठाव के कारण लाभप्रदता में हुई कमी ने ब्याज उपार्जन को प्रभावित किया

4.75 ब्याज दरें घटाने के बावजूद कम ऋण उठाव ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित किया और लाभप्रदता के सभी मुख्य संकेतकों अर्थात् आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) आदि में वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। फिर भी, कम परिचालन व्यय की सहायता से, निजी क्षेत्र के नए बैंक तथा विदेशी बैंक अपनी आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार ला सके।

आस्ति गुणवत्ता के लिए दबाव बना रहा

4.76 2012-13 के दौरान अनर्जक आस्तियों के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। स्लिपेज रेशियो और सकल अग्रिम - पुनर्संचित अग्रिम अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, ज्यादा संख्या में ऋण आस्तियों का "संदिग्ध" वर्गीकरण में बदल जाना अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत अधिक गिरावट को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता में दबाव गैर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों विशेषतः औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना क्षेत्रों के कारण रहा।

पूंजी पर्याप्तता की स्थिति मजबूत बनी रही

4.77 अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति समग्र और बैंक समूह स्तर पर निर्धारित मानकों के ऊपर बनी रही। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी की स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी।

समावेशी बैंकिंग में अधिक प्रगति के संकेत

4.78 वित्तीय समावेशन योजनाओं के तीन साल की समाप्ति पर, शाखा और गैर शाखा माध्यमों से बैंकिंग की पहुंच के विस्तार में काफी अधिक प्रगति होने के संकेत मिले हैं। 2012-13 के दौरान खोली गई नई शाखाओं की कुल संख्या में, अधिकतर शाखाएं 10,000 से कम आबादी वाले टियर 5/6 केंद्रों में खोली गई थीं। वर्ष के दौरान 2000 से ज्यादा आबादी वाले चिह्नित बैकरहित लगभग सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए और वर्ष के दौरान 2000 से कम आबादी वाले बैंकरहित गांवों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में एटीएमों की संख्या बढ़ी है, और श्वेत लेबल एटीएम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने से इन केंद्रों में शाखेतर एटीएमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। फिर भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हो रही चूक चिंता का विषय बनी हुई है, उसका गहरा प्रभाव वित्तीय समावेशन पर भी पड़ रहा है।

4.79 अल्पावधि में आगे बढ़ना है तो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को चाहिए कि वह आर्थिक सुधार में तेज़ी लाने के लिए उत्पादक क्षेत्रों की सहायता करे, लेकिन आस्ति गुणवत्ता के संबंध में सतर्क भी रहे। मध्यम से दीर्घावधि में, इस क्षेत्र को चाहिए कि वह दक्षता और समावेशन में निरंतर सुधार प्रदर्शित करे।